

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

21 मार्च, 1979

खण्ड 1, अंक 12

अधिकृत विवरण

विशय सूची

बुधवार, 21 मार्च, 1979

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्र न एव उत्तर	(12)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(12)21
वैयक्तिक स्पष्टीकरण	(12)29
प्रस्ताव— लोक नायक श्री जय प्रका ा नारायण की भीघ्र अरोग्यता के लिये प्रार्थना करने संबंधी	(12)31
नियम 30 के अधीन प्रस्ताव	(12)35
मेज पर रखे गये कागज पत्र	(12)35
वर्ष 1979-80 के बजट पर आम चर्चा (पुनरारम्भ)	(12)35
वाक आउट	(12)48
वर्ष 1979-80 के बजट पर आम चर्चा (पुनरारम्भ)	(12)48

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 21 मार्च, 1979

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान हाल, विधान भवन,
सैक्टर-1, चंडीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष

(कर्नल राव राम सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: मँबर साहेबान, अब सवाल होंगे।

Checking of floods in Markanda and Tangri rivers

***1132. Shri Devender Sharma:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether any steps have been taken by the Govt. to control the floods in Markanda and Tangri Rivers in Ambala District; and

(b) whether the bunds on both sides of the Markanda and Tangri Rivers have been constructed in Ambala District; if not the time by which those are likely to be constructed?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):

(क) हां।

(ख) हां, इन नदियों पर केवल निचले क्षेत्र और नै नल हाईवे तथा रेलवे पुलों की सुरक्षा के लिये कुछ खाली स्थानों को छोड़ कर।

श्री देवेन्द्र भार्मा: स्पीकर साहब, काले आम पुल से मारकंडा भुरु होता है इससे कुरुक्षेत्र और अम्बाला जिले मे बहुत तबाही हो जाती है। काले आप के पुल से रेलवे लाईन के पुल तक जो जगह खाली रखी गई उसके बारे मे वजीर साहब ने कुछ नही बताया, इस एरिये मे क्या किया जा रहा है, इसको खाली छोड़ने का क्या कारण है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: टांगड़ी और मारकंडा रिवर्ज की लम्बाई बहुत ज्यादा है। किसी वि ेश गांव से दूसरे एक गांव तक या किसी वि ेश जगह से दूसरी लगह तब बताना मु ि िकल है लेकिन सवाल के जवाब मे सब कुछ बता दिया है कि कुछ गैप्स छोड़े गये है। इन बांधो की एम्बैंकमेंट का काम भी अब तक हो चुका है।

श्रीमती सुशमा स्वराज: मारकंडा और टांगड़ी नदियों के बांध का मंत्री महोदय ने वर्णन किया है, उन दोनों बांधों के अलावा कोई और योजना भी अम्बाला को बाढ़ से बचाने के लिये सरकार विचाराधीन है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह: जो जरूरी ड्रेन्ज है वह भी साथ ही निकाली जा रही है लेकिन इन दोनो बांधों से और इनकी एम्बैकमेंट से काफी फर्क पड़ेगा।

श्री फतेह चंद विज: जैसा कि मंत्री महोदय ने फरमाया है कि इन नदियों के पानी से हाईवे की हिफाजत के लिये काफी बड़े गैप्स छोड़े गये है क्या इन गैप्स की वजह से तो तबाही नही हो रही है और क्या इन गैप्स को फिल अप करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह: इस बार तो अन प्रैसीडेंटिड फ्लड आये है, इन दोनो रिवर्ज मे तकरीबन एक लाख क्यूसिक पानी का बहाव रहा है। इस बारे मे महकमा पूरी तरह से जागरूक है। जो गैप्स छोड़े गये हे उनको फिल उप किया जा रहा है।

चौधरी ई वर सिंह: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि मारकंडा और टांगड़ी नदियों की बाढ़ को नियंत्रित करने का कोई प्रबंध किया गया है ? मारकंडा और टांगड़ी अम्बाला से आगे घग्घर मे मिल जाती है इन तीना के मिलने से बहाव बहुत तेज हो जाता है। जिससे कुरुक्षेत्र जिले मे बहुत बरबादी होती है। क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी योजना है जिससे इस क्षेत्र को बाढ़ से बचाया जा सकें?

श्री वीरेन्द्र सिंह: इसी लिये तो गैप्स छोड़े गये है ताकि कुरुक्षेत्र न डूबे।

श्री लहरी सिंह मेहरा: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि सरकार के विचाराधीन ऐसी योजना है कि मारकंडा पर बांध बनाया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह: बांध का जवाब तो मैंने पहले ही दे दिया है। पानी को स्टोर करने के लिये दो बैराज बनाये जा रहे हैं जिनका काम 1980 में हाथ में लिया जायेगा।

चौधरी राजेन्द्र सिंह: मारकंडा और टांगड़ी नदियों बरि गो के दिनों में काफल बड़े क्षेत्र में किसानों की फसल को तबाह कर देती है। क्या कोई योजना सरकार के विचाराधीन है कि इस फालतु पानी को इकट्ठा करके उस पानी को खेती के लिये इस्तेमाल किया जाये?

श्री वीरेन्द्र सिंह: मैंने जिक्र किया है कि पानी को स्टोर करने के लिये दो बैराज बनाये जा रहे हैं एक मारकंडा पर एक टांगड़ी पर।

चौधरी उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, मैं पहले भी मंत्री महोदय के नोटिस में लाया था कि हर आदमी अपने इलाके में बांध बंधवाना चाहता है। तो कहीं ऐसा न हो कि सारे का सारा पानी मेरे इलाके बादली में आ जाये। जब तक दिल्ली सरकार जमना पर पुल बनाने का प्रबंध नहीं करती इस मारकंडा और टांगड़ी के पानी को वहीं का वहीं रखा जाये ताकियह आकर

बादली मे तबाही न करे। मैं मंत्री जी से यह भी कहूंगा कि ड्रेज का काम चलते रहना चाहिए।

श्री वीरेन्द्र सिंह: मैं माननीयम मेंबर साहब को यकीन दिलाता हूं कि टांगड़ी और मारकंडा का पानी बादली मे बिल्कुल नही जायेगा।

डा. बृज मोहन गुप्ता: मारकंडा और टांगड़ी नदियों मे अम्बाला केंट के पहले ही बहुत से छोटे छोट नदी नाले मिल जाते है। सढौरा मे यह नदी बहुत खतरनाक हो जाती है और जगाधरी हल्का मे बहुत तबाही मचाती है, पिछले साल भी बहुत तबाही हुई है। क्या इसे ख्याल मे रखते हुए सरकार का इन ड्रेन्ज को पक्का बनाने का विचार है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह: ड्रेन्ज के बारे मे इस समय कुछ नही बताया जा सकता।

मास्टर िव प्र ाद: मारकंडा और टांगड़ी नदियों के अलावा घग्घर नदि पर बांध बनाने का कोई प्रोग्राम है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह: इस समय नही है।

चौधरी भागमल: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो बांध बनाये जा रहे है वे किस किस जगह बनाये जा रहे है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: सरदारपुर मे टांगड़ी पर और घनोरा गांव मे मारकंडा पर पुल बनाये जा रहे है।

श्रीमती सुशमा स्वराज: आई.पी.एम. साहब ने जवाब में बताया है कि रेलवे पुल की हिफाजत के लिये खाली जगह छोड़ी गई है परन्तु हकीकत यह है कि यही रेलवे पुल बांध बनाने में आड़े आ रहा है । मंत्री महोदय क्या रेलवे मंत्री और पी.डब्ल्यू.डी. वालों से बात करके इस रेलवे पुल को ऊंचा करवायेंगे ताकि हम भी अपना बांध बनवा सकें ?

श्री वीरेन्द्र सिंह: हम रेलवे मंत्री और पी.डब्ल्यू.डी. वालों से एप्रोच कर रहे हैं ।

श्री देवेन्द्र भार्मा: अध्यक्ष महोदय, अम्बाला जिले के लोगो की सढ़ौरा से मुलाना तक हर साल हजारो किल्ले जमीन ये नदिया तबाह कर देती है । क्या सरकार ने लोगो को इस तबाही से बचाने के लिये कोई इंतजाम किया है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह: गैप्स इसीलिये छोड़े जाते हैं ताकि पानी से नीचे के लैवल के क्षेत्रों की तबाही न हो सके कुरुक्षेत्र में बिल्कुल तबाही न हो उसकें लिये ये गैप्स जरूरी हैं ।

Amount as Land Revenue

***982. Chaudhri Jagit Sing Pohloo:** Will the Minister for Revenue be pleased to state to total amount received as Land Revenue in the State during the period from 1-4-78 to 31-1-79?

राजस्व मंत्री (श्री प्रीत सिंह): भू-राजस्व को समाप्त करने पर खरीफ 1973 से लैण्ड लागू किया गया है। दिनांक 1-4-78 से 31-1-79 तक कुल 40868639 रुपये लैण्ड होल्डिंग टैक्स के तौर पर वसूल किये गये।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: क्या वजीर साहब बतायेंगे कि वह जो प्रौमिस था, लोगो से वायदे किये गये थे कि सारे किसानो का मुकम्मल तौर पर मालिया माफ कर दिया जायेगा उसका क्या हुआ? तो क्या हरियाणा के किसानो का मालिया माफ करने की कोई प्रपोजल सरकार के विचाराधीन है ?

श्री अध्यक्ष: ऐसी तो कोई बात नहीं है। कोई प्रौमिस नहीं किया गया था कि सारा मालिया छोड़ दिया जायेगा।

चौधरी देस राज: क्या वजीर साहब बतायेंगे कि हरियाणा मे सबसे ज्यादा लैण्ड रेवेन्यू किस जिले से आता है ?

श्री प्रीत सिंह: जिला हिसार से सबसे ज्यादा मालिया आता है जो 71 लाख 95 हजार 707 रुपये है।

चौधरी हरस्वरूप बूरा: अध्यक्ष महोदय, टैक्सिज लेने चाहिए लेकिन तब तक जब तक वे इकनॉमिक हो और सरकार को फायदा हो। 1970 के बाद से किसानों से आबियाने पर भारी टैक्स लिये जा रहे हैं। क्या सरकार के विचाराधीन कोई प्रपोजल है कि 1970 से पहले जो टैक्स लगे हुए थे उन्हीं टैक्सिज को दोबारा लागू किया जाये ?

श्री प्रीत सिंह: अब तक ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

Purchase Centres

***1161. Sardar Tara Singh:** Will the Minister for Food and Supplies be pleased to state—

(a) the number of purchase centres recently sanctioned for the Kurukshetra district togetherwith the location and the time by which such centres are likely to be set up; and

(b) whether any centres as referred to in part (a) above are to be set up in village Cumthala etc. in Kurukshetra district?

खाद्य तथ पूर्ति मंत्री (चौधरी गजराज बहादुर नागर):

(ए) कुरुक्षेत्र जिला मे वर्ष 1978-79 मे भागल, ठोल तथा गुमथलागरु पर तीन खरीद केन्द्र खोलने के

आदे ा जारी किये गये थे। दो केन्द्रों पर इस वर्ष गेहूं की खरीद की गई थी। गमथलागरू पर खरीद केन्द्र अगले वर्ष चलने की सम्भावना है, जबकि मार्किट कमेटी द्वारा आव यक सुविधायें उपलब्ध की जायेगी।

(बी) हां।

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साह, क्या मंत्री महोदय की जानकारी मे यह बात हे कि इस साल कुरुक्षेत्र जिले के बहुत सारी फसल पंजाब की मण्डियों मे बिकी है ? तो क्या मंत्री जी यह महसूस नही कर रहे कि परचेजिंग सेंटर कम होने के कारण हरियाणा की मण्डियों का अनाज हरियाणा के साथ लगने वाली पंजाब की मण्डियो मे बिका है?

चौधरी गजराज बहादुर नागर: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह नही बताया कि कौन सी मण्डी को वे रैफर कर रहे है?

सरदार तारा सिंह: अध्यक्ष महोदय, कुरुक्षेत्र जिले की फसल खसत करके पेहवा मण्डी के साथ लगने वाले इलाके की फसल पंजाब की मण्डियों मे बिकी है। क्या मंत्री महोदय के नोटिस मे यह बात है, अगर है तो क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि हरियाणा की मण्डियो का अनाज पंजाब की मण्डियों मे जाकरन बिके और हरियाणा के किसानो को कोई नुकसान न हो?

चौधरी गजराज बहादुर नागर: अध्यक्ष महोदय, पिछली दफा सरकार को जितनी भी ऐसी सूचनाएं मिली है उनके अनुसार ऐसी तो कोई बात नहीं है लेकिन मेरे साथी मੈंबर ने ही सूचना दी थी कि गुमथला मण्डी मे खरीद नहीं हो सकी। इसका कारण यह था कि पहले कुछ मार्किट कमेटियो ने सरकार को इस बारे मे सहयोग देना था जो कि वह इस साल नहीं दे पाई इसलिये वहां पर खरीद नहीं हो सकी। इसलिये उनका माल पंजाब की मण्डियों मे जा करके बिका था।

चौधरी राम किान: अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि यह परचेजिंग सटर खोलने का सरकार का क्या क्राइटरिया है?

चौधरी गजराज बहादुर नागर: अध्यक्ष महोदय, परचेजिंग सेंटरन खोलने के लिये पहले तो मार्किट कमेटी हमें कुछ जगह तैयार करके देती है। जहां पर परचेजिंग सेंटर खोले जायेंगे वहां पर सबसे पहली बात तो जगह की है दूसरे वहां पर कच्चे पक्के खाल बनेंगे और वहां मार्किट कमेटी बिजली पानी आदि का प्रबंध करेगी तथा वहां मार्किट कमेटी का स्टाफ होगा। जब इन बातों का प्रबंध हो जाता है तो हम वहां पर परचेजिंग सेंटर खोल देते है।

श्री भामेेर सिंह: अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय बताने की कुपा करेंगे कि जिल जींद मे दमतान और दातासिंह, दो

गांव है क्या वहां पर परचेजिंग सेंटर खोलने की स्कीम सरकार के विचाराधीन है?

चौधरी गजराज बहादुर नागर: अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात हाउस के नोटिस में ला देता हूँ कि बहुत बड़ी तादाद में इस साल मण्डियों का हम निर्माण कर रहे हैं और परचेजिंग सेंटर भी खोल रहे हैं। उनकी लिस्ट तैयार हो रही है। इस समय इसके बारे में नहीं बताया जा सकता क्योंकि लिस्ट मेरे पास नहीं है।

चौधरी गंगा राम: स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि जिन गांवों की आबादी 12 या 15 हजारों की है क्या उन गांवों में भी परचेजिंग सेंटर खोले जायेंगे और इसके साथ साथ मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि जो नई मण्डियां बनेगी क्या उनमें किसानों को दुकानें खोलने के लिये कंसेंट्रेशन रेट पर जगह दी जायेगी ?

चौधरी गजराज बहादुर नागर: अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मंत्री चौधरी देवी लाल जी ने यह फैसला कर लिया है कि देहात में बहुत बड़ी तादाद में मण्डियां बनाई जायेगी और उनमें से बहुत सारी मण्डियां इसी साल एग्जीस्टेंस में आ जायेगी तथा वह गांवों में ही बनाएंगे बाहरों में नहीं।

श्री मंगे राम गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी ने नोटिस में यह बात है कि हरियाणा का गेहूँ पंजाब की मण्डियों में जाकर बिकता है ? उसका कारण यह तो नहीं कि पंजाब की

मण्डियों के भाव ज्यादा होने के कारण हरियाणा की मण्डियों का अनाज वहां पर जाकर बिकता है ?

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया)

श्री रघु नाथ गोयल: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि मेरे हल्के में एक गांव क्योड़क है जिसकी आबादी 16 हजार के करीब है क्या वहां पर मण्डी खोलने की कोई स्कीम सरकार के विचाराधीन है ?

चौधरी गजराज बहादुर नागर: अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मैंने अभी एक सवाल के जवाब में बताया कि इस दफा बहुत बड़ी तादाद में मण्डियों खोलने जा रहे हैं और परचेजिंग सेंटर भी खोले जायेंगे जिनकी लिस्ट तैयार हो रही है अगर माननीय सदस्य किसी खास जगह के बारे में पूछना चाहते हैं तो मुझे अलग से लिख कर करके दे दे इनको सूचना दे दी जायेगी।

श्री जगन नाथ: अध्यक्ष महोदय मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि भिवानी जिले में एक बवानीखेड़ा तहसील है वहां पर कोई मण्डी नहीं है लेकिन लोगों से चारे का टैक्स लिया जा रहा है। अगर वह चारा टैक्स नाजायज लिया गया है तो क्या वह चारा टैक्स वापित करने की कृपा करेंगे?

चौधरी गजराज बहादुर नागर: अध्यक्ष महोदय, इस सवाल का इससे कोई संबंध नहीं है। अगर मेरे साथी चाहते हैं तो लिख करके दे दे। इसके बारे में इनको सूचना दे दी जायेगी।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): अध्यक्ष महोदय, यह चारा टैक्स कैनल एक्ट के तहत म्यूनिसिपल कमेटियों द्वारा चार्ज किया जाता है। इस चारा टैक्स से संबंधित जो रूल है उसको कंसिडर किया जा रहा है भायद हम इससे पीछा छुड़वा दें।

चौधरी उदय सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय की जानकारी में है कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो गेहूं की क्वालिटी निर्धारित की जाती है उस वजह से कई बार किसानों की गेहूं रिजैक्ट कर दी जाती है और इससे उसे काफी परे ानी का समाना करना पड़ता है ? हमारे पड़ोस में पंजाब स्टेट वाले सब किसानों को उनकी गेहूं का पूरा भाव दे रहे हैं तो क्या हरियाणा में भी इस पर अमल किया जायेगा ताकि किसानों को परे ानी न हो?

चौधरी गजराज बहादुर नागर: अध्यक्ष महोदय, पिछली दफा ऐसी रिक्वायत आई थी कि गेहूं साफ नहीं है इस वजह से कोई ऐसा केस हो सकता है लेकिन इस बार हमने 12 मण्डियों के गेहूं साफ करने वाली मशीनों का प्रबंध कर दिया है और मुझे मार्किट कमेटियों के चेयरमैनो ने आवासन दिया है कि इस बार ऐसी रिक्वायतों का मौका नहीं दिया जायेगा।

श्री भले राम: अध्यक्ष महोदय, जैसे मंत्री जी ने बताया कि बड़े बड़े गांवों में मण्डियां खेली जायेंगी क्या मंत्री महोदय यह

भी बताने की कृपा करेंगे कि जिन गांवों के पास मण्डियों के लिये जमीन नहीं है वहां जमीन एक्वायर करेंगे या गांव वालों को देनी पड़ेगी ?

चौधरी गजराज बहादुर नागर: अध्यक्ष महोदय, मण्डी खोलते वक्त हर चीज का ध्यान रखा जाता है। जो मेरे साथी ने डिवैल्पमेंट की तरफ ध्यान दिलाया है, इसका भी ध्यान अव य रखा जायेगा।

स्वामी अग्निवे I: स्पीकर साहब, मण्डियों की आमदनी पहले जनरल पूल में डाल देते थे और वह कहीं पर भी खर्च की जा सकती थी, लेकिन अब मुख्य मंत्री जी ने फैसला किया है कि मण्डियों की आमदनी का 70 परसेंट रूपया मार्किट कमेटी के उसी इलाके की भलाई के लिये खर्च किया जायेगा। क्या मंत्री महोदय इस घोशणा पर 1 अप्रैल से अमल करना आरम्भ कर देंगे ?

श्री अध्यक्ष: यह सवाल मार्किट कमेटियों का नहीं है, परचेज सेंटर खोलने का है।

चौधरी गजराज बहादुर नागर: जब लीडर आफ दी हाउस ने एक बात कह दी है तो उस पर जल्दी से जल्दी अमल किया जाएगा लेकिन किस तारीख से इस पर अमल होगा, इसके लिये तारीख फिक्स करने की पोजी उन में मैं इस वक्त नहीं हूँ क्योंकि इस प्र न का संबंध मूल प्र न से नहीं है।

चौधरी देस राज: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने कहा कि सारे हरियाणा में परचेज सेंटर खोले जा रहे हैं। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि करनाल डिस्ट्रिक्ट में कहां कहां खोले जा रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: आप नोटिस दे दे, मंत्री जी जरूर बता देंगे

चौधरी लाल सिंह: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि नारायणगढ़ और कालका में भी किसी मण्डी खोलने का विचार है?

श्री अध्यक्ष: इसका नोटिस दे दे, बता देंगे।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: स्पीकर साहब, मण्डियों में दो दो हफ्ते तक अनाज बाहर पड़ा रहता है, अनाज बिकता नहीं है। इस तकलीफ को मद्देनजर रखते हुए और सरकार ने जो स्पोर्ट फिक्स किया है उसको ध्यान में रखते हुए गांव गांव में मण्डियां खोलने का विचार है ताकि किसान को स्पोर्ट प्राईस पूरी मिले ?

चौधरी गजराज बहादुर नागर: मण्डियां बनाने का विचार तो जरूर है लेकिन गांव गांव में जाकर खरीदने की तजवीज सरकार के जेरेगोर नहीं है।

Roads constructed in Barwala Constituency

***976. Shri Jai Narain Verma:** Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) the number alongwith the length of roads and the new roads which have been constructed during 1978-79 to date in Barwala Constituency; and

(b) the total number of roads proposed to be constructed in Barwala Constituency during the next financial year?

लोक निर्माण मंत्री (श्री लछमन सिंह):

(ए) (I) पहले से निर्माणाधीन सड़के	2
लम्बाई जो बनाई गई	2.65

कि.मी.

(II) नई सड़के जो आरम्भ की गई	3
------------------------------	---

अर्थवर्क जो नई सड़कों पर किया गया	5.90
-----------------------------------	------

कि.मी.

(बी) उपरोक्त 5 सड़कों को मिला कर 9 सड़कों पर कार्य प्रगति में होगा।

श्री जय नारायण वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया कि पुराने जमाने से निर्माणाधीन सड़कें 2 हैं, 3 नई सड़कें और बनाने के लिये हाथ में ली हैं और 4 सड़कों पर अभी काम

भरु करना है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि उन 4 सड़कों के क्या क्या नाम हैं जिनको बनाना भरु कना है?

श्री लछमन सिंह: मेरे पास लम्बी लिस्ट है, अगर आप कहें तो मैं पढ़ देता हूँ।

श्री अध्यक्ष: उचित यही होगा कि आप लिस्ट मेंबर साहब को दे दें (व्यवधान) वैसे मंत्री जी ने जवा बदे दिया हे कि इतनी किलोमीटर सड़क बन गई है, कहां से कहां तब बनी है, इसमे रैस्ट आफ दी हाउस का इन्ट्रैस्ट नहीं है। (व्यवधान)

श्री जय नारायण वर्मा: स्पीकर साहब, बरवाला से जींद की सड़क मुद्दत से निर्माणाधीन है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि यह सड़क कितने सालों से पेंडिंग पड़ी हुई है और कब तक बनाकर पूरी करेंगे ?

श्री लछमण सिंह: बरवाला से जींद तक 19.61 किलोमीटर सड़क है। 16.61 किलोमीटर सड़क 31.3.79 तब बन जायेगी और जो बकी रहेगी उसको बनाने की जल्दी से जल्दी कोर्ि । । करेंगे । (विधन)

चौधरी हरस्वरूप बूरा: स्पीकर साहब, गांव को सड़क से मिलाने के लिये जो सड़कें बनी हुई है, वे फिरनी के नजदीक जाकर छोड़ दी गई है और इस वजह से कहीं कहीं पर दो दो, तीन तीन किलोमीटर का रास्ता रह गया है। क्या मंत्री महोदय ऐसी सड़कों को फिरनी तक बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री लछमन सिंह: फिरनी की सड़के मेरा महकमा नही बनाता, इनको बनाना पंचायत का काम है। हम तो गांव के साथ कुनैक्ट करते है, इसके आगे गांव की चौड़ी गलियां बगैरा गांव की पंचायत बनाती है।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, लतानी और दूजनपुर गांवों मे 5 साल पहले सड़कें बनी थी लेकिन इनमे मिसिंग लिंक्स है। क्या सरकार की कोई ऐसी स्पीम है जिसके तहत इन मिसिंग लिंक्स को अनया जाये, अगर स्कीम है तो कब तक बनाया जायेग ?

श्री लछमन सिंह: इस लिस्ट मे इन गांवो के नाम नही है, मैं पता करके बता दूंगा।

सदरार सुखदेव सिंह: स्पीकर साहब, रु कंडल से खोरी वाया हरजीपुर सड़क पिछले 30 सालों से नही बनी। इस सड़क को बनाने की मंजूरी पहले तो दे देते है लेकिन बाद मे रद्द कर देते है। क्या मी महोदय इस सड़क को बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री लछमन सिंह: इस वक्त तो बरवाला कांस्टीयूएँसी का मामला अंडर कंसीड्रे ान है, इसके लिये अलग नोटिस दीजिए।

श्री जगन नाथ: स्पीकर साहब, भिवानी जिले की बवानीखेड़ा तहसील पिछले पांच साल साल पहले बनी थी, इसके बारे मे सी.एम. साहब को भी पता है और दूसरे मंत्री साहेबान भी

जानते हैं कि तहसील हैडक्वार्टर पर काफी दफतर बन गए हैं, लेकिन इसके पश्चिम की तरफ 50 किलोमीटर की पूरी तक लोगों को तहसील में आने जाने के लिये सड़कें नहीं हैं। कई सड़कें बनी हुई हैं लेकिन बीच-बीच में कई टुकड़े नहीं बने हैं और लोगों को भिवानी से होकर तहसील में आना पड़ता है। कुछ लोग हिसार और हांसी से होकर आते हैं। क्या सरकार ऐसी सड़कों को बनाने के लिये टॉप प्रियोरिटी देगी ?

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, सी.एम. साहब ने हाउस में यह अयोरेंस दी थी कि 1982 के इलैक्शन में जो लोग वोट लेने के लिये किसी गांव में पैदल आये तो उसको वोट मदद दो (हांसी) स्पीकर साहब, अर्ज यह है कि बहुत सारी सड़कें सिंगल लिंक की बनी हैं और बहुत सी डबल लिंक की हैं। यह पोजीशन सारी स्टेट में है। हम पहले सिंगल लिंक को बनाने में प्रिोरिटी देते हैं और इसके बाद डबल लिंक को बनाते हैं अगर कहीं पर सिंगल लिंक मिसिंग हो तो बता दें, हम उसको गौर करेंगे।

श्री अध्यक्ष: देखिए, मैं मैनबर साहेबान का ध्यान फिर एक महत्वपूर्ण बात की ओर दिलाना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि बड़े-बड़े जरूरी सवाल होते हैं लेकिन यह आप मानेंगे कि बरवाला और बवानी खेड़ा का आपस में काफी फासला है। इस लिये मेरे सवाल से संबंधित जो सप्लीमेंटरी हो उसी तक मैनबर साहेबान अपने आपको सीमित रखने की कृपा करें (गौर) आर्डर प्लीज, आर्डर।

श्री दीप चंद भाटिया: स्पीकर साहब, सदरार साहब 1982 की बात कर रहे हैं लेकिन आपके द्वारा मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 1982 किसने देखा है? पता नहीं 1982 तक हम जिन्दा रहेंगे, यह हाउस जिन्दा रहेगा या जिन्दा नहीं रहेगा (हंसी और भाँर)

श्री लछमन सिंह: कुछ होने वाला नहीं है । हम जिन्दा रहेंगे । (गोर व व्यवधान)

(इस समय चौधरी लाल सिंह तथा कई अन्य सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए।)

श्री अध्यक्ष: चौधरी लाल सिंह जी आप बैठिये । (गोर) देखिए, मैं मँबर साहेबान से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि हाउस मे कृपया कोई ऐसी बात न कहे जो हाउस की भाान के खिलाफ हो । (विघ्न)

चौधरी लाल सिंह: स्पीकर साहब, कई गांव गवर्नमेंट की डायरैक्टरी मे नहीं हैं उनकी आबादी बहुत ज्यादा है लेकिन उनको अभी तक कोई सड़के नहीं मिली इसलिये मैं आपकी मारफत माननीय मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहता हूँ कि ऐसे गांव की सड़कों पर कब तक काम भुरू होगा क्योंकि अफसरों से जब हम इसके बारे मे बात करते है तो वे कहते है कि उनके पास ऐसा करने के आर्डर नहीं है ?

श्री अध्यक्ष: मेन प्र न से इस सप्लीमेंटरी का कोई संबंध नहीं है।

(इस समय बहुत से सदस्य प्र न पूछने के लिये खड़े हुए।)

Mr. Speaker: Last supplementary by Shri Jai Narain Verma.

स्वामी आग्निवे T: अध्यक्ष महोदय, इस प्र न के बारे में हाउस यह चाहता है कि इस पर आधे घंटे की डिस्कशन होनी चाहिए।

Mr. Speaker: Please give it to me in writing. I will consider it.

श्री जय नारायण वर्मा: स्पीकर साहब, बरवाला से जींद सड़क पर एक पुल बनने को है, इसपुल की वजह से इस सड़क का काम भी रुका पड़ा है। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस पुल कारे बनवा कर इस सड़क को कब तक पूरा करवा देंगे ?

श्री लछमन सिंह: तारीख तो नहीं बताई जा सकती लेकिन मैं इसका पता करूंगा।

Block Development Officers

***1036. Dr. Brij Mohan Gupta:** Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state—

(a) the total number of Block Development Officers appointed after the formation of Janata Govt. in the State; and

(b) the criterion followed for the appointment of such Officers?

विकास मंत्री (ठाकुर बीर सिंह):

(ए) 19 (उन्नीस)

(बी) खंड विकास तथा पंचायत अधिकारियों की 70 प्रतिशत रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा हरियाणा लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर तथा 30 प्रतिशत समाज विरुद्ध तथा पंचायत अधिकारियों को पदोन्नति भरी जाती है। भर्ती के लिये रखी योग्यता सदन के पटल पर रखी जाती है।

अनुबंध

हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से खंड विकास तथा पंचायत अधिकारियों के पद पर सीधी भर्ती द्वारा लगाने के लिये योग्यताएं:-

किसी भी व्यक्ति की सीधी भर्ती नहीं की जायेगी यदि वह निम्नलिखित योग्यताएं न रखता हो:-

- (ए) किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय का स्नातक हो।
- (बी) हरियाणा सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किया गया हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए
- (सी) कृषि फार्म पर बतौर परोगरैसिव फारमर दो वर्ष का तजुर्बा रखता हो अथवा दो वर्ष का कृषि का काम करने का अनुभव और खेलों में रुचि अतिरिक्त योग्यता होगी।

नोट:-

- (1) परोगरैसिव किसान के लिये ऊपर धारा (सी) में दिये गये अनुभव के लिये उपायुक्त से प्रमाण पत्र लेना जरूरी है।
- (2) ऊपर धारा (सी) में दी गई भर्ती एक्स्टेंशन आफिसर कृषि, सहकारिता, समाज शिक्षा

तथापंचायत तथा विलेज उद्योग मे 5 साल के तजुर्बा रखने वाले को छूट दी जा सकती है। भूतपर्व सैनिको को, यदि उन्हें कृषि का प्रैक्टिकल ज्ञान हो, इस योग्यता से छूट दी जा सकती है।

(3)खेलो मे रूचि का अर्थ है कि उम्मीदवार को हाई स्कूल कालेज या टीम या किसी दूसरी मान्यता प्राप्त टीका मेंबर होना चाहिए।

(4)भूतपूर्व सैनिकों का अर्थ केवल कमी गन्ड आफिसर से है तथा इसमे इसमे एन.सी.ओ. तथा कलैरिकल काम मे लगे व्यक्ति नही आते है।

उमर:- 25 से 35 साल होनी चाहिए। उमर मे डिजविंग केसों मे छूट दी जा सकती है और सरकारी कर्मचारियों को 40 साल तक व भूतपूर्व सैनिकों को 45 साल तक छूट दी जा सकती है।

विभाग के समाज शिक्षा व पंचायत अधिकारियां को खंड विकास तथा पंचायत अधिकारी के पद पर पदोन्नति करने के लिये योग्यता:-

पदोन्नती द्वारा भरे जाने वाले बी.डी.पी.ओ. के पद एस.ई.पी.ओ. की पदान्ति से भरे जाते है। एस.ई.सी.ओ. को बी.डी.पी.ओ. के पद पर पदोन्नति पाने के लिये स्नातक होना अनिवार्य है परन्तु इस भारत मे उन एम.ई.पी.ओ. को ढील दे दी जाती है

जिनकी बतौर सो ल एजुके ान आरगेनाईजर/पंचायत आफिसर/एस.ई.पी.ओ. पांच वर्ष सेवा हो चुकी हो ।

डा. बृज मोहन गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मेरे प्र ान के पार्ट (ए) के उत्तर मे मंत्री जी ने 19 जवाब दिया है । मैं उनसे यह जानना चाहूंगा कि क्या ये 19 बेकैंसीज जनता सरकार बनने के बाद क्रिएट हुई या पहले से भी कुछ चली आ रही थी और दोनो मिल कर के 19 बन गई ?

ठाकुर बीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, क्राइटेरिया तो जेसा मैंने अभी बताया 70 परसैंट और 30 परसैंट का हे लेकिन पिछली सरकार ने भर्ती सीधे करने की वजाय ऐडहौक बेसिज पर कर दी और 22 स्थान ऐडहौक बेसिज पर भर लिये । बाद मे 1975 मे 19 जगहें खाली हुई जिसके लिये पब्लिक सर्विस कमी ान ने जनवरी 1978 मे अप्वायंटमेंट करके कैंडिडेटस की लिस्ट पोस्टिंग के लिये डिपार्टमेंट के पास भेज दी । (विघ्न)

डा. बृज मोहन गुप्ता: स्पीकर साअ, 70 और 30 परसैंट के क्राइटेरिया के मुताबिक डायरैक्ट रिक्रूटमेंट की 16 वेकैंसीज बनती है । क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इनमे से उन्होंने कितनी वेकैंसीज डायरैक्ट रिक्रूटमेंट से फिलअप की और कितने कैंडिडेटस ऐम्पलायमेंट ऐक्सचेंज के थ्रू आए है?

ठाकुर बीर सिंह: स्पीकर साहब, मैंने जैसे अभी अर्ज किया कि ये 19 की 19 वेकैन्सीज पब्लिक सर्विस कमी इन के थ्रू फिलअप की गई है। इनमें से तीस परसेंट का सवाल नहीं है। क्राइटेरिया के बारे में जो मैंने अर्ज किया वह दूसरी बात थी। उसके हिसाब से पिछली गवर्नमेंट ने उन स्थानों को नहीं भरा था। 22 पोस्टें उन्होंने वैसे ही भर ली। ये 19 की 19 पोस्टे पब्लिक सर्विस कमी इन के थ्रू भरी गई है। उनमें 16 और 3 का सवाल नहीं है।

चौधरी भागमल: क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इउनमें कितने रिजर्व्ड कास्टस लिये गये और कितने बैकवर्ड क्लासिज के लिये गये? अगर इस बार कोई कमी रह गई है तो क्या वह कोटा आर्यंदा पूरा किया जायेगा?

ठाकुर बीर सिंह: स्पीकर साहब, रिजर्व्ड कास्टस की सैपरेट लिस्ट तो मैंने तैयार नहीं करवाई है। लेकिन मैं प्रिज्यूम करता हूँ कि रिजर्व्ड कोटे को ध्यान में रखते हुए ही पब्लिक सर्विस कमी इन ने सिलैक इन की होगी। फिर भी मैं सदन को यह बता देना चाहता हूँ कि जैसा आर्य जी ने कल एक प्रश्न के जवाब में बताया था, रिजर्व्ड कास्टस के कोटे के बारे में रोजस्टर सिस्टम जारी कर लिया गया है। पहले सरकार में ऐसा नहीं था। जितने रिजर्व्ड कास्टस कंडिडेटस लिस्ट पर होंगे उनका नम्बर नैचुरली आयेगा। इस सिस्टम के अनुसार अब ऐसा है कि 2 परसेंट कोटे के मुताबिक जितने कंडिडेटस का नम्बर

पड़ता हो, वे ले लिये जाते हैं। बाकी जो रह जाते हैं वे नैक्सट टाईम में लिये जाते हैं। अब सिक्की का हक नहीं माना जायेगा। (प्र. संसा) मिसाल के तौर पर 19 सीटों में से चार सीटें डिप्लोमेटिक कास्टस को मिलनी चाहिए। पहले ऐसा होता था कि खाली वेकेंसीज के अगेन्सट अगर उन्हें नहीं लिया जाता है तो उनका हक खत्म हो जाता था और नई पोस्टिंग के वक्क उनका फिर हक बनता था लेकिन अब जो रोस्टर सिस्टम बनाया गया है इसके मुताबिक उनका हक खत्म नहीं होगा। सरकारी पालिसी के मुताबिक जिनका हक बनता जायेगा उनको वह मिलता जायेगा।

कंवर रामपाल सिंह: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने अभी बताया कि 70 परसेंट डायरेक्ट रिक्लूटमेंट से आते हैं और 30 परसेंट प्रमोशन से आते हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि इन 19 पोस्टस में प्रमोशन वालों का कितना कोटा है? क्या प्रमोशन वालों को कोई सीट मिली है या नहीं मिली है ?

श्री अध्यक्ष: इसका जवाब ये दे चुके हैं। If the Hon. Minister still wants to clarify any point he may do so.

ठाकुर बीर सिंह: मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ ताकि कोई गलत फहमी न रह जाये। ये तो 19 की 19 पोस्टस पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू भरी गई है। मैंने यह बताया था कि 70 और 30 का जो क्राइटेरिया था इसे पिछली सरकारने पूरा नहीं किया था 14-11-78 तक जो पोजीशन थी वह यह थी कि

डासरैक्ट रिक्लूटमेंट तो 36 की थी और प्रमोटिड 53 रह गये । इसमे 66 परसेंट जो है वह डायरैक्ट रिक्लूटमेंट के जरिऐ से हो गये और 34 परसेंट प्रमो इन से हो गये । यह जो 4-4 का गैप है इसको पूरा कर दिया जायेगा ।

चौधरी राजेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, एक ब्लाक मे एक ही बी.डी.ओ. लगता है परन्तु आजकल कई ब्लाकों मे दो दो बी.डी.ओ. लगे हुए है जिसके कारण से काम सुचारु रूप से नही चल रहा है । मैं मिनिस्टर महोदय से जानना चाहता हूं कि दो लगाने का क्या कारण है और कितने समय तक एक ब्लाक मे एक ही बी.डी.ओ. के आर्डर कर दिये जायेंगे ?

ठाकुर बीर सिंह: यह बात बिल्कु ठीक है । 19 बी.डी.ओ. की रिक्लूटमेंट पब्लिक सर्विस कमी इन के जरिये हुई । इन की जगह पर जो 17 बी.डी.ओ. एडहोक पर लगे हुए थे उनको रिवर्ज कर दिया गया । उन मे से 15 ने हाई कोर्ट मे रिट दायर कर दी । वहां से रिट खारिज हो गई और उनके रिवर्न के आर्डर हो गये लेकिन फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से स्टे हासिल कर लिया । अब एक तो जो हमने अप्वायंट किये, वे चले गये और दूसरे जो वहां एडहोक पर लगे हुए थे वे भी सुप्रीम कोर्ट के स्टे के मुताबिक जा बैठे । इस तरह से यह कम्पलीके इन पैदा हो गई । इस बारे मे हमरने एल.आर. के और एडवोकेट जनरल के दफतर से भी सलाह ली है । हमारे एडवोकेट जनरल ने जो हमारी सुप्रीम कोर्ट मे वकील है उसको कहा है कि जल्दी से जल्दी स्टे वैकेंट कराओ

ताकि दो की जगह पर एक ही लगाया जा सके। हम इस बारे में पूरी कोशिश कर रहे हैं।

श्री जय नारायण वर्मा: स्पीकर साहब, अभी मिनिस्टर साहब ने आरिखत कोटे की सुरक्षा की बात कही है, मैं उसके लिये उनको बधाई देता हूँ लेकिन मैं मिनिस्टर महोदय से जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से रिजर्वेड कास्ट के लिये 20 परसेंट रिजर्वेशन है इसी प्रकार से सरकार ने बैकवर्ड क्लासिज की भी रिजर्वेशन 2 परसेंट से पांच परसेंट कर दी है। क्या वही रोस्टर सिस्टम बैकवर्ड क्लासिज के लिये अपनाया गया है, यदि अपनाया गया है तो ये कौन से नम्बर पर आते हैं ?

ठाकुर बीर सिंह: अब नम्बर क्या बताऊँ। रोस्टर बना हुआ है उसके मुताबिक नम्बर आ जायेगां

श्री अध्यक्ष: मिनिस्टर साहब ठीक फरमा रहे हैं कि अगर 20 एम्पलाई लेंगे तो एक बैकवर्ड का भी नम्बर भी जरूर आयेगा।

डा. बृज मोहन गुप्ता: अभी मिनिस्टर ने जवाब दिया है कि 19 पोस्टस तो पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा भरी गई हैं परन्तु मैं मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहता हूँ कि इनमें से कितनी पोस्टस एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के थ्रू भरी गईं और कितनी डायरेक्ट भरी गईं ?

ठाकुर बीर सिंह: सारी की सारी पोस्टस पब्लिक सर्विस कमीशन से भरी गई हैं।

चौधरी हरस्वरूप बूरा: मैं मिनिस्टर महोदय से जानना चाहता हूँ कि तजन लोगो को रिवर्ट लिया था और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया है यानी रिट एक्सैप्ट हो गई तो क्याउनको नये ब्लाक खोल कर एडजैस्ट किया जायेगा?

ठाकुर बीर सिंह: स्पीकर साहब, जो जयादतियां पिछली सरकार ने की है, उनको देखते हुए हमारे लीडर आफ दी हाउस ने हयूमन कंसिड्रे ान दी है। (गोर व विघ्न)

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी जवाब दे रहे है इसलिये भान्तिपूर्वक सुनना चाहिए।

ठाकुर बीर सिंह: स्पीकर साहब, पिछली सरकार ने उस क्राइटेरिया को तोडत्र कर एडहोक पर भर्ती कर ली और इधन सन् 1975 मे पब्लिक सर्विस कमी ान ने 19 पोस्टें एडवरटाइजमेंअ करके भर ली। गवर्नमेंट के पास पोस्टर केवल 17 थी जबकि एडहोक पर 22 पहले ही लगाये हुए थे। इस तरह से यह झगड़ा पड़ गया लेकिन फिर भी हमारे लीडर आफ दी हाउस ने हयूमन कंसिड्रे ान रखी कि जो एडहोक पर दो साल काम कर चुके है उनको भी एडजैस्ट कर दिया जाये। उन को म्युनिस्पल कमेटियों मे डिमिनिस्ट्रेटर की आफर दी गई परन्तु उन्होंने साफ इंकार कर दिया। जहां तक उनको एडजैस्ट करने का सवाल है, पहले एडहोक वालो की रिव र्तिन के आर्डर हुए है इसलिये वहां एडजैस्ट

करने का ता सवाल ही नहीं है। ज्यो ज्यो पोस्टस आयेगी उनको प्रमोट कर दिया जायेगा।

श्री बलदेव तायल: स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस सवाल के 'ख' भाग की ओर दिलाना चाहता हूँ। उन्होंने उत्तर में फरमाया है कि खंड विकास तथा पंचायत अधिकारियों की 70 परसेंट रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा हरियाणा लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर तथा 30 परसेंट रिक्खा तथा पंचायत अधिकारियों की पदोन्नति द्वारा भरी जाती है। भर्ती के लिये रखी योग्यता सदन के पटल पर रखी जाती है। मंत्री महोदय ने केवल एजैन्सी बताई है कि पब्लिक सर्विस कमीशन की मार्फत चुने गये हैं लेकिन नियुक्ति के लिये क्या योग्यता या मापदण्ड अपनाया गया है उसके बारे में एक भी भाव नहीं कहा है। क्या उनकी योग्यता के बारे में भी बतायेंगे ?

ठाकुर बीर सिंह: मेरे लायक दोस्त इस बात को जरूर जानते होंगे कि पब्लिक सर्विस कमीशन जब पोस्ट एडवर्टाईज करता है तो उसमें क्वालिफिकेशन भी दी हुई होती है लेकिन फिर भी मैंने सदन के पटल पर सारी इंफॉर्मेशन रखी है।

Creation of additional post of Inspector General of Police

***1136. @Lala balwant Rai Tayal:** Will the Minister for Irrigation and Power be please to state whether two additional posts in the rank of Inspector General of Police

have been created on the transfer of the former Inspector General of Police; if so, the justification therefor?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):

(क) यह ठीक है कि भूतपूर्व पुलिस महा निरीक्षक के स्थानान्तरण पर राज्य में पुलिस महानिरीक्षक के रैंक में दो अतिरिक्त पद बनाए गए हैं।

(ख) यह दोनों अतिरिक्त पद प्रशासकीय कारणों से बनाए गए हैं।

श्री मांगे राम गुप्ता: मंत्री जी ने सवाल के जवाब में बताया है कि प्रशासन के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये दो एडी जनरल आई.जी. बनाये गये हैं। मैं मिनिस्टर महोदय से जानना चाहता हूँ कि अब जो एडी जनरल आई.जी. को आई.जी. जेल लगाया है, क्या प्रशासन का काम ठीक तरह से निभा सकेंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिंह: अगर आपको नजर आती है तो बताये।

श्री भामदेर सिंह: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि ती आई.जी. लगाने के बाद ला एंड आर्डर की स्थिति में सुधार आया है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा सदन को बताना चाहता हूँ कि आई.जी. पुलिस की एक ही पोस्ट है और

हमे 11 से एक ही रही है। दो आई.जी. जो प्रमोट किये है वे एक्स कैंडर पोस्टस पर प्रमोट किये है। जहां तक ला एंड आर्डर की स्थिति है उसके बारे मे अभी खुद मेरे से तारीफ करके गये है कि आपका इंतजाम कमाल का था।

श्री सुमेर चंद भट्ट: स्पीकर साहब, आई.जी. की एडी इनल पोस्ट क्रिएट करने के बारे मे इरीगे इन एंड पावर मिनिस्टर साहब की और से जवाब दिया जा रहा है। मैं आपके थू यह जानना चाहता हं कि क्या होम का महकमा इरीगे इन डिपार्टमेंट मे मर्ज हो गया है? क्या यह अनोमलैस सी बात नही लगती है कि होम डिपार्टमेंट का ताल्लुक तो होम मिनिस्टर से है लेकिन जवाब आई.पी.एम. साहब दे रहे है ? इसी तरह से हैल्थ मिनिस्ट साहिबा प्रिंटिंग एंड स्टे इनरी का जवाब देती है, तो यह अनोमलैस पोजी इन क्यों है, इसका इलाज क्यों नही किया जाता है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, नोमिनक्लेचर फिक्स करना चीफ मिनिस्टर साहब का काम है कि किस मिनिस्टर को क्या विभाग देना हे और किस लान से जाना जाये ? अगर प्र न पूछने वाला सदस्य होम मिनिस्टर कह करके भी पूछेगा तो भी मैं जवाब दे दूंगा।

Providing of Veterinary facilities in the State

***1101. Chaudhri Shiv Ram Verma:** Will the Minister for Cooperation and Dairy Development be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the govt. to provide veterinary facilities to the people in the State of Haryana; if so, the steps so far taken or proposed to be taken in this behalf?

सहकारिता तथा दुग्ध विकास मंत्री (चौधरी भजन लाल): जी हां, हरियाणा राज्य के लोगों को पशुधन केन्द्रों, स्थिर एवं चलती फिरती वैटनरी डिस्पेंसरियां/हस्पतालों के माध्यम से पशु चिकित्सा की सुविधाएं दी जा रही हैं। वर्ष 1978-79 में 30 नई वैटनरी डिस्पेंसरियां खाली गई हैं और वर्ष 1979-80 में 20 और ऐसी डिस्पेंसरियां खोलने का प्रस्ताव है। वर्ष 1978-79 में 10 वैटनरी डिस्पेंसरिया और 10 पशुधन केन्द्रों को वैटनरी हस्पतालों एवं प्रजनन केन्द्रों, जिनमें पशु चिकित्सक कार्यरत हैं, में परिवर्तित किया गया है और वर्ष 1979-80 में ऐसी 20 और डिस्पेंसरियों को हस्पतालो एवं प्रजनन केन्द्रों में अपग्रेड किया जायेगा। इसके अतिरिक्त वर्ष 1978-79 में राज्य सघन पशु विकास प्रयोजना अम्बाला, जीद, कुरुक्षेत्र तथा भिवानी जिलों में 59 पशुधन केन्द्र बढ़ाए गये हैं और इन केन्द्रों में भी प्रथम पशु चिकित्सा सुविधाएं दी जा रही हैं।

चौधरी शिव राम वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बड़ा लम्बा जवाब पढ़ कर हमें सुना दिया है। मैं उनसे यह पूछना चाहूंगा कि पिछले साल तो उन्होंने 30 डिस्पेंसरियां खोली, उससे

अगले साल इन्होंने 20 डिस्पेंसरियां खोलने का प्रोवीजन रखा है। इस रफतार से पंजुओं का इलाज किस तरह से सुविधाजनक हो सकेगा क्योंकि आदमी अगर बीमार हो तो उसको तो साइकिल पर या किसी और चीज पर बिठाकर ले जाया जा सकता है लेकिन यदि यह पंजु बीमार हो तो एक गांव से दूसरे गांव में ले जाना भी मुश्किल होता है? क्या मंत्री महोदय हर गांव में पंजु चिकित्सालय खोलने का प्रबंध करेंगे ?

चौधरी भजल लाल: अध्यक्ष महोदय जैसे तो हमने पिछले साल भी 20 डिस्पेंसरियां ही खोलनी थीं लेकिन फंडज की वजह से हमने 10 डिस्पेंसरियां और खोलने के लिये फाइनेंस डिपार्टमेंट से रुपया मांगा। इन्होंने रुपया दिया इनकी बड़ी मेहरबानी। हर साल हम 20 डिस्पेंसरियां खोलते हैं। लेकिन अगर हमें फंडज और ज्यादा मिल जायेंगे तो हम और ज्यादा डिस्पेंसरियां खोलेंगे। मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना भी करूंगा कि हमें कुछ फंडज और ज्यादा अलाट करें ताकि हम और डिस्पेंसरिया खोल सकें।

चौधरी हरस्वरूप बूरा: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने नई डिस्पेंसरिया भी खोली है और कुछ अपग्रेड भी की है। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या जो वे नयी डिस्पेंसरियां खोलते हैं या कोई अपग्रेड करते हैं, उनके लिये उनके पास पूरा स्टाफ अवेलेबल है या नहीं ?

चौधरी भजल लाल: अध्यक्ष महोदय जब हम डिस्पेंसरी खोलते हैं या किसी को अपग्रेड करते हैं तो स्टाफ का इंतजाम करने के बाद ही करते हैं।

श्री मूल चंद जैन: क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे, जैसे कि उन्होंने यह बताया कि दूसरे जिलों में तो इन्होंने काफी डिस्पेंसरियां खोली हैं, गुड़गांव जिले में, जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है, एक भी डिस्पेंसरी इन्होंने नहीं खोली है। वह जिला ऐसा है जहां पर बाढ़ भी आती रहती है जिसकी वजह से पशुओं को बीमारियां लगती रहती हैं, क्या वहां पर कोई नयी डिस्पेंसरी खोलने पर विचार करेंगे ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं मैनबर साहेबान की जानकारी के लिये यह बताना चाहता हूं कि गुड़गांव जिले में हमने सबसे ज्यादा डिस्पेंसरियां खोली हैं। भारत सरकार की एक स्कीम है जिस के तहत हमने 1966 से लेकर आज तक के 100 के करीब डिस्पेंसरियां अकेले गुड़गांव जिले में खोली हैं।

श्री अध्यक्ष: मैनबर साहेबान की अपने अपने जिले के बारे में जो एनगजायटी है, उसको तो मैं एप्रीयियेट करता हूं लेकिन कम से कम फैक्ट्स और फिगरज के आधार पर यहां पर सवाल पूछने चाहिये। मंत्री जी ने जैसे बताया है कि गुड़गांव जिले में ज्यादा से ज्यादा डिस्पेंसरियां खोली हैं तो इस तरह से हाउस का टाईम जाया नहीं करना चाहिए।

स्वामी आग्निवे T: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जैसे उन्होंने बताया है कि फंडस बड़े सीमित है इसलिये हर जगह अभी डिस्पेंसरी खोली नहीं जा सकती क्या जब तक स्टाकमैन सेंटर या डिस्पेंसरी हर गांव में नहीं बनाई जाती, तब तक कोई मोबाईल डिस्पेंसरी बगैरा खोलने का विचार है या विचाराधीन है जिससे कि गांव के लोगों को रोज नहीं तो दूसरे तीसरे दिन उनके पंजुओं के इलाज के लिये सुविधा हो सके ?

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छा सुझाव है।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, 19 चलते फिरते हमने खोल रखे है। तकरीबन हर जिले में ऐसे चलते फिरते हस्पताल है। यह हस्पताल है। यह हस्पताल बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे है।

चौधरी हरि चन्द हुड्डा: मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जो पंजु डिस्पेंसरियां इन्होंने खोली है, इनके खोलने का क्या क्राइटेरिया है ? क्या यह लोगों की आजादी के ऊपर या पंजुओं की आबादी के ऊपर खोली जाती है ? (हंसी) अगर पंजुओं की आबादी के ऊपर खोली जाती है तो मेरे यहां खंडवाली गांव है, उसमें पंजु गाला है जिसमें लगभग 3-4 हजार पंजु है, क्या वहां पर खंडवाली में एक हस्पताल खोलने पर विचार करेंगे ?

चौधरी भजन लाल: पहले तो हुड्डा साहब को एक बात में बताऊं कि आदमियों के लिये हस्पताल खोले जाते हैं आदमियों के आधार पर और पशु चिकित्सालय पशुओं की गणना के आधान पर। अगर कोई आदमी बीमार पड़ जाये उसे क्या पशुओं के डाक्टर के पाल इलाज के लिये ले जायेंगे ? जहां तक इन्होंने क्राइटेरिया पूछा है और उसका ताल्लुक है, कोई गांव वाले बिल्डिंग वगैरा बनाकर दे दें तो हम वहां पर डिस्पेंसरी खोल देते हैं यदि पशुओं की गणना ज्यादा हो और बहुत ही नजदीक और कोई दूसरी डिस्पेंसरी खोल देते हैं यदि पशुओं की गणना ज्यादा हो और बहुत ही नजदीक और कोई दूसरा अस्पताल न हो तो।

चौधरी देस राज: क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि हरियाणा में कितने पशु हैं, कितने दूध देते हैं, उनमें कितनी गायें हैं और कितनी भैंसे हैं।

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, स्टेट में कुल 69 लाख 50 हजार पशु हैं जोकि 1977 की जनगणना के आधार पर है। इनमें से 49 लाख 70 हजार दूध देने वाले हैं। इनमें 24 लाख 50 हजार गायें हैं और 25 लाख 20 हजार भैंसे हैं।

चौधरी उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंग कि जो फलड अफैक्टिड एरियाज है, वहां पर 4-5 महीने तक तो आने जाने के

रास्ते बंद रहते हैं, क्या उन इलाकों में प्रायरीटरी बेसिस पर अस्पताल खोलने पर सरकार विचार करेगी?

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, जैसे कि मैंने हाउस में पहले बताया है कि 20 डिस्पेंसरियां हमारा खोलने का पिछले साल प्रोग्राम था। लेकिन फलड की वजह से 11 डिस्पेंसरियां हमने और खोली हैं जोकि फलड अफैक्टिड एरियाज में ही खोली हैं।

चौधरी हुक्म सिंह: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने यहां पर यह फरमाया है कि जो गांव बिल्डिंग बनाकर देंगे, हम वहां पर डिस्पेंसरी खोल देंगे, क्या सरकार के कोई ऐसी प्रोजेक्ट विचारधीन है कि जो गांव बिल्डिंग बनाकर नहीं दे सकते हैं, वहां पर बिल्डिंग सरकार बनाये?

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, सरकार के विचाराधीन इस किसम की कोई प्रोजेक्ट नहीं है। जैसे स्कूल खुलवाने के लिये गांव में भवन बनाकर गांव वालों को बनाकर देना पड़ता है वैसे ही डिस्पेंसरी खुलवाने के लिये भी वहां पर भवन बनाकर गांव वालों को देना पड़ेगा।

श्री जगत नाथ: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी ने यह पूछना चाहता हूँ कि इनकी नौलेज में क्या यह बात है कि हिसार के अंदर संजय गांधी अपने कुत्ते का इलाज करवाने के लिये आये थे ? अगर आये थे तो क्या उनके कुत्ते का इलाज हुआ या नहीं

हुआ ? इलाज होने के बाद क्या उन्होंने युनिवर्सिटी में भी एड्रेस किया था ?

श्री अध्यक्ष: कुत्ते का इलाज करवाने के लिये कोई आया था या नहीं इसका इस सवाल से कोई संबंध नहीं है।

चौधरी भजन लाल: इसके बारे में तो होम मिनिस्टर साहब ही बता सकते हैं कि संजय गांधी आये थे या नहीं आये थे।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): स्पीकर साहब, जहां तक संजय गांधी के आने का सवाल है, मैं बतौर होम मिनिस्टर यह बताता हूँ कि वह आया जरूर था जहां तक कुत्ते के इलाज करवाने का सवाल है, वह ये बतायेंगे ? (हंसी) (व्यवधान व भाोर)

कैप्टन मांगे राम: मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या उनका किसी फलड अफैक्टिड एरिया में कोई नयी डिस्पेंसरी खोलने का विचार है अगर है तो मेरे हल्के में भिंडावास में जहां पर मंत्री महोदय अभी अभी एलान करके आये हैं कि वहां पर डिस्पेंसरी बनाएंगे वहां पर कब तक स्टाफ भेज देंगे ?

चौधरी भजन लाल: अप्रैल के दूसरे हफ्ते में वहां पर स्टाफ भेज दिया जायेगा।

चौधरी विव राम वर्मा: स्पीकर साहब, पिछले कुछ दिनों से हम यह सुनते आ रहे हैं कि अगर किसी जगह इतनी

जनसंख्या होगी तो वहां पर स्कूल खोल दिया जायेगा, अगर इतनी जनसंख्या होगी तो हस्पताल खोल दिया जायेगा। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजु चिकित्सालय खोलने के बारे भी कोई सीमा निर्धारित करके हर जगह पर पंजु चिकित्सालय खोलने के बारे में कोई विचार किया जायेगा ?

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, सारी बात फाइनेंस पर डिपेन्ड करती है। अगर धन की उपलब्धि हो गई तो पूरी कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पंजु चिकित्सालय खोले जाये। यह बात ठीक है कि आदमी अगर बीमार हो जाये तो दूसरी जगह जाकर इलाज करवा सकता है लेकिन पंजु के बारे में ऐसा करना बड़ा कठिन है। हमारी पूरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा पंजु डिस्पेंसरियां खोली जायें लेकिन सारी बात फाइनेंस पर डिपेंड करती है।

Mr. Speaker: Question Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों

के लिखित उत्तर

Upgradation of Food and Supplies Department

***1112. Shri Devender Sharma:** Will the Minister for Food and Supplies be pleased to state with reference to the reply to Starred Question No. 296 given on the 28th February,

1978, whether the Govt. order declaring the Food and Supplies Deptt. as 'A' Class Office has been implemented, if not, the reasons therefor?

खाद्य तथा पूर्ति मंत्री (चौधरी गजराज बहादुर नागर):
जी हां, श्रीमान जी। आदेश कार्यान्वित किये जा चुके हैं।

Taking over for Schools

***1068. Chaudhri Jagjit Singh Pohloo:** Will the Minister for Education be pleased to state—

- (a) the names of the schools which were taken over during the Emergency period;
- (b) the steps taken or proposed to be taken to compensate the management of said schools; and
- (c) the steps taken or contemplated to be taken to compensate the employees who suffered on this score?

शिक्षा मंत्री (श्री हीरा नंद आर्य):

(ए) एमरजेंसी के दौरान जो विद्यालय सरकार द्वारा टेक ओवर किये गये थे, वे निम्नलिखित हैं:—

(1) बी.एल.हाई. स्कूल, खोल (नारनौल)।

(2) बाल आश्रम जनता प्राइमरी स्कूल, जींद।

(3) कैंट बोर्ड हाई स्कूल अम्बाला छावनी तथा इसकी छः प्राईमरी ब्रांचे ।

(4) हरियाणा भोखावती ब्रह्मचर्य आश्रम, भिवानी ।

(बी) कोई कम्पैसे ान नही दिया जाता क्योंकि सरकार द्वाराये स्कूल उनकी प्रबंध कमेटी की प्रार्थना पर टेक ओवर किये गये थे ।

(सी) उपरोक्त पैरा 'बी' मे वर्णित स्थिति के आधार पर प्र न उत्पन्न नही होता ।

Appointment of Naib Tehsildars

***1037. Dr. Brij Mohan Gupta:** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the number of Naib Tehsildars appointed in the State after the formation of Janata Govt. upto 31&1&1979;

(b) the number of appointments out of those referred to in part (a) above which have been made though the Subordinate Service Selection Board; and

(c) the number of such appointments as have been made with consultation of the S.S.S. Board?

राजस्व मंत्री (श्री प्रीत सिंह):

(ए)	नियमित	84
	तदर्थ	2
	कुल	86
(बी)	42	
(सी)	42	

Sales Tax Tribunal

***1137. Lala Balwant Rai Tayal:** Will the Minister for Excise and Taxation be please to state—

- (a) the yearwise number of appeals recived by the Sales Tax Tribunal since its inception of date;
- (b) the number of case out of those referred to in part (a) above in which the decisions have been announced so far;
- (c) whether the judgements in the cased referred to in part (b) above have been communicated to the concerned parties; and
- (d) if not, the reasons therefor?

आबकारी तथा कराधान मंत्री (चौधरी भोर सिंह):

(ए) तथा (बी) सूचना (स्टेटमेंट) विधान सभा पटल पर रखी जाती है।

(सी) जी, हां।

(डी) प्र न उत्पन्न नहीं होता।

स्टेटमेंट

	(ए)	(बी)
वर्ष	न्यायाधिकरण की स्थापना होने से अब तक प्राप्त अपीलों की संख्या	भाग (ए) में वर्णित किये गये केसों में से निर्णय लिये गये केसों की संख्या
1	2	3
31-3-68 तक	107	
1968-69	309	416
1969-70	249	249
1970-71	224	223
1971-72	251	251

1972-73	284	275
1973-74	289	175
1974-75	362	224
1975-76	341	103
1976-77	307	64
1977-78	295	33
1978-79 (28-2-79 तक)	142	2
1-3-79 से 7-3-79	4	7
कुल जोड़:	3064	2025

Provision of Drinking Water

***1102. Chaudhri Shiv Ram Verma:** Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to provide drinking water under the water supply scheme to the villages where drinking water is injurious to health due to water logging; and

(b) if so, the detail thereof?

लोक निर्माण मंत्री (श्री लछमन सिंह):

(ए) नहीं जी।

(बी) प्र न पैदा नहीं होता।

**Promotion as Deputy Superintendent in the Education
Departement**

***1134. Captain Mange Ram:** Will the Minister for Education be pleased to state whether any person belonging to the Scheduled Castes has been promoted as Deputy Superintendent in the Education Directorate on the basis of "Reservation for Scheduled Castes" after coming into being of the State of Haryana; if so, the number thereof ?

शिक्षा मंत्री (श्री हीरा नंद आर्य): नहीं।

Re-employment of J.B.T. Teachers

***1010. Shri Jai Narain:** Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to provide Govt. jobs in the State to those J.B.T. Teachers who passed their training course in the last years, if so, the details thereof ?

शिक्षा मंत्री (श्री हीरा नंद आर्य): जी नहीं।

Posting of Works Managers in Haryana Roadways Depot

***1156. Shri Mange Ram:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that Works Managers in all Haryana Roadways Depots are posted in the State; and

(b) if reply to part (a) above be in the negative, the names of the Depots where the Works Managers have not been posted and the reasons therefor in each case?

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल):

(क) नहीं।

(ख) हरियाणा राज्य परिवहन गुड़गांवा के सब डिपो देहली, सिरसा, चण्डीगढ़, कैथल तथा भिवानी में एक एक कार्य प्रबंधक के पद यानी 5 पद खाली है। इन पदों को पदोन्नति द्वारा भरने के केस सरकार के विचाराधीन है।

Provision of Drinking Water in the State

***1139. Shri Fateh Chand Vij:** Will the Minister for Public Works be pleased to state the district wise number of villages where the facility of drinking water has been provided during the period from 1-4-77 to 31-3-78 and 1-4-78 to 31-12-78, separately?

लोक निर्माण मंत्री (श्री लछमन सिंह): जिन गांवों में 1-4-77 से 31-3-78 तथा 1-4-78 से 31-12-78 तक पीने के पानी की सुविधा प्रदान की गई है, का जिलेवार ब्यौरा:—

क्र.	जिले	का	1-4-77 से 31-3-78 तक जिन गांव में पीने	1-4-78 से 31-12-78 तक जिन गांव में पीने

	नाम	के पानी की सुविधा प्रदान की गई।	के पानी की सुविधा प्रदान की गई।
1.	अम्बाला	20	7
2.	भिवानी	6	2
3.	गुड़गांव	20	—
4.	हिसार	29	2
5.	जींद	5	1
6.	करनाल	2	—
7.	कुरुक्षेत्र	—	—
8.	महेन्द्रगढ़	30	32
9.	रोहतक	4	—
10.	सिरसा	8	11
11.	सोनीपत	1	—
	कुल जोड़:	125	55

Audit of the Cooperative Sugar Mills in the State

***1118. Rao Dalip Singh:** Will the Minister for Cooperation and Dairy Development be pleased to state—

(a) whether the accounts of the Cooperative Sugar Mills in the State have been audited during the year 1978-79;

(b) whether any embezzlement case have been detected in the Cooperative Sugar Mills during the year 1978-79; and

(c) if so, a copy each of the Audit Reports be laid on the Table of the House?

सहकारिता तथा दुग्ध विकास मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) राज्य की सहकारी चीनी मिलों के लेखों के वर्ष 1978-79 में अभी तक आडिट नहीं हुए हैं क्योंकि ये 30-6-79 के पश्चात ही आडिट के लिये देय होंगे।

अपित्तु सोनीपत, करनाल और रोहतक सहकारी चीनी मिलों के वर्ष 1976-77 के लेखों वर्ष 1978-79 में आडिट किये गये हैं। रोहतक चीनी मिल का वर्ष 1977-78 का आडिट कार्य प्रगति पर है। पानीपत सहकारी चीनी मिल के वर्ष 1976-77 के लेखों का आडिट चल रहा है और आडिट जल्दी पूर्ण हो जायेगा।

(ख) नहीं जी।

(ग) ऊपर (ख) के उत्तर के कारण प्र न नहीं उठता।

**Abolition of English languages as compulsory subject in
the Schools**

***1127. Swami Agnivesh:** Will the Minister for Education be pleased to state whether the Government is considering to abolish English language as a compulsory language in the Schools in the State as recommended by the Haryana School Education Board; if so, the steps, if any, taken or proposed to be taken in this respect ?

शिक्षा मंत्री (श्री हीरा नंद आर्य): नहीं प्र न ही पैदा नहीं होता।

Land for Sehgal Paper Mills as Dharuhera

***1083. Rao Ram Narain:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state—

(a) the total area in acres in possession of Sehgal Paper Mills at Dharuhera at present;

(b) the number of lots in which the said area of land has been acquired by the State Government for Sehgal paper Mills giving Nos. of notifications under sections 4 & 6 of the Land Acquisition Act;

(c) the area in their possession when Janata Party Government come into power;

(d) the area they got possession, after assumption of office by Janata Party Government; and

(e) whether it is a fact what they have applied for getting more area?

कृषि मंत्री (ब्रिगेडियर रण सिंह):

(ए) 178.50 एकड़।

(बी) मैं 0 सहगल पेपर मिलज लि 0 को धारूहेड़ा मे 4 भिन्न भिन्न लाटों मे भूमि नियतन की गई है जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र.	नियतन की गई भूमि	अधिसूचना की क्रमांग तथा तिथि		अवार्ड की तिथि
		धारा-4	धारा-6	
1	69.68 एकड़	एल.ए. ओ / 74 / 3314, 22-10-74	एल.ए.ओ. (पी)-75 / 5390, 2-12-75	29-1-7 6
3	11.60 एकड़	एल.ए. ओ / 74 / 3314,	एल.ए.सी.-75 / 6904, 26-5-75	17-9-7 5

		22-10-74		
4	22.97 एकड़	एल.ए. ओ / 74 / 3314, 22-10-74	एल.ए.सी. (पी)-77 / 146, 13-1-77	11-10- 77
5	24.25 एकड़	एल.ए. ओ / 74 / 3314, 22-10-74	एल.ए.सी. (पी)-77 / 4433, 17-10-77	6-7-78

(सी) 69.68 एकड़ ।

(डी) 108.82 एकड़ ।

(ई) हां। सहगल पेपर मिल्ज लि० ने अपने कर्मचारियों के आवास के लिये रिहाय गी प्रयोग हेतु 121 एकड़ भूमि नियतन करने के लिये प्रार्थना की है ।

**Extension to the Chairman/Members of the Haryana State
Electricity Board**

***1151. Shri Kanwal Singh:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to give extension to the present Chairman or any

Member of the Haryana State Electricity Board,
and

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative,
the reasons therefor?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):

(क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्र न नहीं उठता।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण

श्री बलदेव तायल: अध्यक्ष महोदय, आन ए पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन। मेरे प्र न के उत्तर में विकास तथा पंचायत मंत्री महोदय ने फरमाया था कि भायद सदस्य को यह पता न हो कि पब्लिक सर्विस कमीशन के क्या फंक्शन हैं। स्पीकर साहब, इस बारे में मैं मंत्री महोदय को कुछ तथ्यों से अवगत कराना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि मंत्री महोदय को विदित होना चाहिए कि हर पोस्ट को क्वालिफिकेशन सरकार निर्धारित करके पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजती है। पब्लिक सर्विस कमीशन कोई भी क्वालिफिकेशन खुद निर्धारित नहीं करता। पोस्ट भी सरकार ही निर्धारित करती है और क्वालिफिकेशन भी फलां पोस्ट की मिनियम क्वालिफिकेशन क्या होगी। मेरे विचार से

क्वालिफिके ांज के बारे मे मेरे प्र न का जो उत्तर उन्होंने दिया था वह ठीक नही था.....

Mr. Speaker: I have not understood the point. The qualifications etc. prescribed for a post is a public document which is accessible to every one.

विकास मंत्री (ठाकुर बीर सिंह): स्पीकर साहब, मैंने यह कहा था कि जो क्वालिफिके ांज मुकर्रर की गई है, वह सदन की पटल पर रखी हुई है (गोर)

Shri Baldev Tayal: But that reply should have been given in reply to the question.

Mr. Speaker: We should leave to it the Minister how he gives a reply.....

Shri Baldev Tayal: My point arised because he said that the member does not know the working of the Public Service Commission....

श्री अध्यक्ष: ऐसा कैटेगरीवली उन्होंने नही कहा है।

ठाकुर बीर सिंह: मैंने तो यही कहा था कि क्वालिफिके ांज सदन की पटल पर रखी हुई है। (गोर)

श्री बलदेव तायल: स्पीकर साहब, पब्लिक सर्विस कमी ान क्वालिफिके ांज मुकर्रर नही करता, सरकार मुकर्रर करती है (गोर) And that fact is not known to the Minister.

श्री अध्यक्ष: फ़ैक्ट तो यह होगा कि गवर्नमेंट इन कंसलटे इन विद पब्लिक सर्विस कमी इन क्वालिफिके इंज निर्धारित करती है। (गोर)

Shri Baldev Tayal: It is normally the Government which fixes the qualifications and not the Public Service Commission. The Minister does not know this fact. (Interruptions)

ठाकुर बीर सिंह: स्पीकर साहब, मैंने अपने लायक दोस्त के सवाल के जवाब में यह कहा था कि पोस्ट के साथ उसकी प्रैसक्राब्ड क्वालिफिके इंज पब्लिक सर्विस कमी इन को इंटीमेंट कर दी जाती है जिसको वह ऐडवरटाइज करता है और जो इन पोस्टों के लिये मिनिमम क्वालिफिके इंज थी उनकी लिस्ट पटल पर रखी हुई है और वे पढ़ सकते हैं। मैंने यह नहीं कहा था कि माननीय सदस्य को पब्लिक सर्विस कमी इन को फंक् इंज के बारे में पता नहीं है। मैंने सिर्फ यह कहा था कि मेरे लायक दोस्त क्वालिफिके इंज की लिस्ट जो पटल पर रखी गई है वह पढ़ सकते हैं। (Interruptions)

Mr. Speaker: I would like to close this controversy. Nothing more on it.

Shri Baldev Tayal: I bow before you.

Mr. Speaker: Think you.

श्री भाम गोर सिंह: स्पीकर साहब, आन ए पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन । अभी होम मिनिस्टर साहब ने एक सवाल के जवाब में बातया था कि मैंने जाकर बधाई दी थी। मैं इस अवसर का फायदा उठाने में कोई संकोच नहीं करूंगा। स्पीकर साहब, कल जब, ** * * * (हंसी व गोर)।

Mr. Speaker: It has got no relevance at all. (Interruptions) Nothing should be recorded.

उद्योग मंत्री (डा. मंगल सैन): स्पीकर साहब, मैं आपकी रूलिंग चाहूंगा। हमारे रूलज में जो प्रोविजन है वह यह है कि अगर किसी ने किसी के ऊपर आक्षेप लगाया होक तो पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन के जरिये उसे उसका जवाब देने या स्पष्टीकरण का अवसर प्रदान करना चाहिए। मेरे लायक दोस्त अपने कार्यक्रम के लिये इस फोरम का दुरुपयोग करना चाहते हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि उनके भाब्द कार्यवाही से निकाल दिये जायें (गोर)।

श्री अध्यक्ष: वे बता रहे थे कि होम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा इंतजाम किया.....

डा. मंगल सैन: वे आगे बढ़ रहे थे। वे और भी कुछ कहना चाहते थे कि लोगों ने नाराजगी जाहिर की। (गोर)

स्थानीय भासन मंत्री (चौधरी राम लाल वधवा): स्पीकर साहब, आज सुबह हमने अखबारों में पढ़ा है कि हरियाणा में काले झण्डे दिखाए गए (गोर)।

चौधरी उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, अगर पुलिस फोर्स नहीं होती तो सिर्फ काले झण्डों से ही काम नहीं चलता, लोग पकड़ कर वापिस दिल्ली छोड़ आते (गोर)।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): स्पीकर साहब, जो ऐप्रिसिएशन दी है उसके लिये बड़ी मेहरबानी और जो कुछ साथियों ने बताया है वह भी अखबारों में आया है। लेकिन इनकी नजाकत नहीं गई। कुत्तों का इलाज कराने अब भी हिसार आते हैं (गोर)।

Mr. Speaker: I would request to the hon. Members to take their seats. This is an irrelevant controversy which has nothing to do with the proceedings of the House.

प्रस्वात—

लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण की भीष्म अरोग्यता के लिये
प्रार्थना करने संबंधी

श्री अध्यक्ष: मੈਂबर साहेबा, मेरे पास स्वामी आग्निवेश का एक मोशन आया है जो हमारे लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण की अस्वस्था यानी कि बहुत सीरियस कंडीशन के विषय

मे है। मैं उसको एडमिल करता हूँ और स्वामी अग्निवे । अब अपना मो ।न पढ़े ।

स्वामी आग्निवे ।: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्वात करता हूँ—

कि यह सदन लोकनायक श्री जयप्रका । नारायण के स्वास्थ्य की गम्भीर स्थिति पर भारी चिंता तथा सहानुभूति प्रकट करता है तथा उनके स्वास्थ्य में सुधार तथा उनकी भीघ्र अरोग्यता के लिये ई । वर से प्रार्थना करता हूँ।

Mr. Speaker: Motion moved—

That this House expresses deep concern and have symkpathy on the serious condition of health of Lok Nayak Shri Jayaparakash Narayan and pray God to improvement in his health as well as his early recovery.

स्वामी अग्निवे । (पुंडरी): अध्यक्ष महोदय, हम सब आज सारे दे । के अंदर इस बात से भाकाकुल है, चिन्तित है कि हमारे राष्ट्र नायक, लोक नायक जिन्दगी और मौत के बीच संधर्श कर है। बम्बई के जसलोक हस्पताल में आज वे संकट से गुजर रहे हैं। उनके प्रति दे । के बच्चे बच्चे को सहानुभूति है और सारे का सारा दे । इस बात के लिये हृदय से प्रार्थना कर रहा है कि परमात्मा उनके जीवन की रक्षा करे और उन्हें भीघ्र ही रोग मुक्त करे। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने जोसेवा की, वह किसी पार्टी के लिये अथवा किसी दल वि ।ेश के लिये नहीं की बल्कि सारे राष्ट्र को अंधकार से निकालकर प्रका । की ओर ले जाने में उनका बड़ा

योगदान रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐतिहासिक महत्व है कि चाहे उन्होंने अपना संघर्ष अंग्रेजों के खिलाफ छेड़ा, साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ छेड़ा या दे आ के अंदर जो अन्याय हो रहा था उसके खिलाफ छेड़ा लेकिन उनके नेतृत्व में सारे दे आ ने लड़ाई लड़ी। यही कारण है कि आज सारा दे आ उनके पीछे है और उनके स्वस्थ होने की कामना दे आ का बच्चा बच्चा कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज वे वृद्धावस्था के कारण कुछ बीमारी के कारण, जिन्दगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। उनकी सेवाओं के प्रति हम मत् मस्तिक हैं और मैं समझता हूँ कि सारे सदन की तरफ से उनके जीवन की मंगलकामना के लिये परमात्मा से प्रार्थना की जानी चाहिये (गोर)

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव से अभी सहमत है तो फिर इतनी लम्बी स्पीचें करने का क्या फायदा है (गोर)।

स्वामी अग्निवेश: अध्यक्ष महोदय, यह कोई विवाद का विषय नहीं है जिस पर किसी प्रकार का विवाद खड़ा किया जाये। आज हम सब को लोकनायक श्री जयप्रकाश आ नारायण के स्वास्थ्य के लिये ई वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि ई वर उनको दीर्घ आयु प्रदान करे ताकि वे इस दे आ का और उपकार करने में समर्थ हो सके। इन भाब्डों के साथ मैं ज्यादा न बोलता हुआ एक बार फिर सारे हाउस से प्रार्थना करता हूँ कि हम सब की तरफ से परमात्मा को प्रार्थना की जानी चाहिये कि इस क्रांतिकारी नेता की

दीर्घ आयु हो और वे भीघ्र ही स्वास्थ्य हो। इन भाब्दों के साथ, मैं समाप्त करता हुआ आपका धन्यवाद करता हूँ।

उद्योग मंत्री (डाक्टर मंगल सैन): स्पीकर साहब, स्वामी जी ने लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण जी के स्वास्थ्य के संबंध में जो प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। पटना में वे कुछ दिनों से अकस्मात् बीमार हो गये हैं और वहाँ समर्थन करता हूँ। पटना में वे कुछ दिनों से अकस्मात् बीमार हो गये और वहाँ से उन्हें यान द्वारा बम्बई लाया गया है, जहाँ पर उनका उपचार हो रहा है। स्पीकरसाहब, जसलोक हस्पताल में उनको पहले भी कई मरतबा रखा गया है और अब वहाँ का सारा स्टाफ पूरे प्रयत्नों के साथ इस राष्ट्र के महान नेता, एक क्रांति के अग्रदूत, महान समाजवादी और देश के स्वाधीनता संग्रामियों के सेनापतियों में से एक महान सपूत के जीवन संरक्षण के लिये, उनका जीमन बचाने के लिये संघर्ष कर रहा है, इसके लिये हम सब उन भाईयो के बड़े अभारी हैं। स्पीकर साहब, इस देश की बाल, वृद्ध, नर नारी सभी उस महान सपूत, महान क्रांतिकारी नेता की बीमारी से चिन्तित हैं और सभी उनकी मंगलकामना के लिये भगवान से प्रार्थना करते हैं। इस महान नेता ने अपने यौवन काल में अंग्रेजों की जेलों काटीं, 'भारत छोड़ो आंदोलन' के दिनों में भूगत आंदोलन का नेतृत्व किया। स्पीकर साहब, हम भी जेलों में गये और हम कल्पना कर सकते हैं कि जेलों से भागना कोई आसान बात नहीं है। हजारी बाग भूगत

आंदोलन का भी उन्होंने नेतृत्व किया। इस दे 1 में जब एक दिन निरा 11 छा गई, हाथ को हाथ हनी दिखता था, उस वक्त इन्होंने छात्र आंदोलन जैसे आंदोलन खड़े किये। अपातकाल की घोशणा हुई, दुर्भाग्यव 1 उन्हें चण्डीगढ़ के हस्पताल में ही रखा गया। उसी वक्त से उनको किडनी ट्रबल है। उनकी किडनी खराब हुई है, यह उन्ही दिनों की मुसीबत उनको दी हुई है जिसके साथ वे इस समय संघर्ष कर रहे हैं। मैं अधिक न कहता हुआ परमपिता परमात्मा से यह प्रार्थना करूंगा कि उस महान नेता की दीर्घायु हो। चाहे भगवान हमारे जीवन का भोश भाग भी ले ले, पर वे भीघ्र ही स्वस्थ हो जाये। स्पीकर साहब, जब ज्यादा न कहता हुआ अपने सदन से मैं प्रार्थना करूंगा कि हम सब को मिलकर उनकी जीवनरक्षा की मंगलकामना करनी चाहिए और इस प्रस्ताव को जो स्वामी जी ने प्रस्तुत किया है, सर्व सम्मति से से पारित किया जाना चाहिए।

श्री भाम 1ेर सिंह (नरवाना): अध्यक्ष महोदय, अभी स्वामी जी ने लोकनायक श्री जयप्रका 1 नारायण जी के स्वास्थ्य लाथ के लिये जो प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत किया है, उसका मैं अपने साथियों की तरफ से समर्थन करता हूं। श्री जयप्रका 1 नारायण जी 1942 की क्रांति के हीरो थे और उसके बाद उनका सारा जीवन इस दे 1 के लिये और इस दे 1 की जनता के लिये ही बीता। वे पिछले तीन चार रोज से गम्भीर रूप से जसलोक हस्पताल में बीमार है। अध्यक्ष महोदय, सारा दे 1 उनके स्वास्थ्य

के बारे में बहुत चिंतित है और परमात्मा से यह प्रार्थना करता है कि भगवान उनको दीर्घायु प्रदान करें। भिन्न भिन्न पार्टियों और संस्थाओं की ओर से उनके स्वास्थ्य लाभ के लिये परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है कि वह उनको लम्बी आयु प्रदान करें। इसके साथ-साथ में इस सारे सदन के जरिये अपनी सरकार से यह कहूंगा कि इस सदन की तरफ से एक रेजोल्यूशन पास करके केन्द्र सरकार को भेजा जाये कि लोकनायक जी के स्वास्थ्य लाभ के लिये चाहे जितना भी रुपया खर्च क्यों न आये, उनके इलाज के लिये किसी की कोई कमी न दोड़ी जाये, हर तरह से उनकी मदद जिससे कि वे भीघ्र ही स्वस्थ हो सकें। कि ई वर उनको दीर्घायु दे और वे लम्बे अर्से तक इस संसार में जीवित रहें और इस दे की सेवा करते रहे।

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल): स्पीकर साहब, आज के दिन लोकनायक बाबू जयप्रकाश नारायण जी की बीमारी के कारण सारा दे की चिन्तित है कि एक ऐसा भाख्स जिसने बगैर कसी स्वार्थ के जीवन भर सेल्फलैस सर्विस की हो, वह आज मौत और जिन्दगी के संघर्ष में मुबतला है जिस पर आज पूरे दे की चिंता है। 1942 की क्रांति में जो पार्ट उन्होंने अदा किया, वह सब को याद है लेकिन इनकी ऐसी हालत को देखते हुए भी हम सिवायें परमात्मा से उनके लिये प्रार्थना करने के, बेबस हैं। हम तो परम पिता परमात्मा से केवल यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी दीर्घायु करें ताकि वह इस दे की ओरसेवा कर सकें। इन

भाबदों के साथ मैं स्वामी जी के इस प्रस्वाव का समर्थन करता हूँ जोकि उन्होंने इस हाउस मे पे । किया है । हाउस की यह कामना है कि ई वर उनको जिंदगी दे और उनको इलाज मे भाफा मिले ।

Mr. Speaker: Hon. Members leaving politics aside, there is no doubt that Lok Nayak Jayparkash Naryana is one of the most outstanding personalities that this country has ever produced. I would like to associate myself with the deep concern whown by all sections of this House in his present predicament and serious illness. We can at this stage only pray to God Almighty to give him strength in the battle that he is waging between life and death, and I join the House in praying the Almighty for given him strength and courage to win the battle that he is fighting. And, taking the sense of the House, I take it that this resoluion moved by Swami Agnivesh is unanimously passed.

(Vices: Yes)

Mr. Speaker: Thank you. The motion is unamiously passed.

नियम 30 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष: अब मंत्री महोदय नियम 30 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।

वित्त मंत्री (श्री मूल चंद जैन): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ—

कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 30 को निलम्बित किया जाये तथा वीरवार 22 मार्च, 1979 को सरकारी कार्य किया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत किया हुआ—

कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 30 को निलम्बित किया जाये तथा वीरवार 22 मार्च, 1979 को सरकारी कार्य किया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्र न है—

कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 30 को निलम्बित किया जाये तथा वीरवार 22 मार्च, 1979 को सरकारी कार्य किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

मेज पर रखे गये कागज—पत्र

उद्योग मंत्री (डा. मंगल सैन): अध्यक्ष महोदय, हरियाणा तथा पंजाब कृषि वि विद्यालय अधिनियम, 1970 की धारा 39(3) के अंतर्गत मैं आपकी अनुमति से हरियाणा कृषि वि विद्यालय, हिसार की वर्ष 1976-77 की वार्षिक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखता हूँ।

चौधरी हरस्वरूप बूरा: स्पीकर साहब, मेरा एक काल अटैन्- इन मो इन था उसका जवाब 19 तारीख को आना था लेकिन अभी तक नहीं आया है।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): स्पीकर साहब, उसका जवाब मैं 23 तारीख को दूंगा।

वर्ष 1979-80 के बजट पर आम चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष: अब साल 1979-80 के बजट पर फिर से चर्चा भुरू होगी। श्री राम कि इन जी अपनी स्पीच जारी करें।

चौधरी राम कि इन (सफीदों): स्पीकर साहब, कल मैं कह रहा था कि जैन साहब ने जो बजट सदन के सामने रखा है वह बहुत अच्छा बजट है। अपोजी इन के भाइयों ने भी इस पर हुई बहस में हिस्सा लेते हुए काफी चर्चा की।

स्वामी आदित्यवे T: अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्र न है। पिछले दिनों हाउस में आ वासन दिलाया गया था कि यह पूरा प्रयास किया जायेगा कि जितनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की जायेंगी वे हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाशाओं में दी जायेगी। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हिसार कृषि वि विद्यालय की जितनी भी रिपोर्ट है ये सारी अंग्रेजी में ही है, हिन्दी में नहीं है। क्या इसके बारे में कोई प्रबंध किया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष: इस संबंध में गवर्नमेंट ने आर्डर कर दिये हैं लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने में अभी कुछ टाइम लगेगा। यह रिपोर्ट पिछले पीरियड से संबंधित है। अगली रिपोर्ट के बारे में मैं गवर्नमेंट से रिकवैस्ट करूंगा कि वह दोनों भाषाओं में होनी चाहिए।

चौधरी राम किान: स्पीकर साहब कुछ अपोजीान के साथियों ने कहा कि यह बजट ऐंटी किसान बजट है और 85 प्रतिान देहात में रहने वाले लोगों के खिलाफ है लेकिन ऐसी बात नहीं है। यह बजट बाबू जी ने बहुत तैयारी करके यहां पर प्रस्तुत किया है। बाबू जी इस मामले में बहुत ज्यादा अनुभव रखते हैं। मैं इसका हृदय से समर्थन करता हूं। इसके साथ साथ मैं हाउस के लीडर को तथा वित्त मंत्री को यह प्रार्थना करता हूं और हाउस की भी यह सैंस है कि गरीब किसानों पर और गरीब आदमियों पर जो दस परसेंट आबियाना लगाया है और जो 33 प्रतिान लैंड होल्डिंग टैक्स परसरचार्ज लगाया है इस पर पुनर्विचार किया जाये। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य, चौधरी प्रताप सिंह ठाकरान, पदासीन हुए) इसके अलावा गरीब आदमियों पर जो रजिस्ट्रेशन का खर्चा बढ़ाया गया है इस पर भी पुनर्विचार किया जाये। कल राव दलीप सिंह जी ने अपने भाषण में भ्रष्टाचार की चर्चा की। जो आदमी किसी को रिगत लेते पकड़वाएगा उसे पांच सौ रूपया ईनाम मिलेगा लेकिन चेयरमैन साहब मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी प्रार्थना करूंगा कि

यह जो पांच सौ रूप्ये की राशि है यह बहुत कम राशि है यह बहुत कम है। इसी वजह से आज तक रिवत लेने वाले को पकड़वाने के लिये कोई आगे नहीं आया इसलिये अगर इस राशि को पांच सौ रूप्ये की बजाये पांच हजार कर दिया जाये तो अच्छा होगा। इसके अलावा मैं मुख्य मंत्री जी को इस बात के लिये भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने हमारे जींद जिले की तरक्की की तरफ भी ध्यान दिया है। इस सरकार के वजूद में आने से पहले किसी भी सरकार ने जींद की तरक्की की तरफ ध्यान नहीं दिया था। अब तक वहां पर कोई मिनि सैक्रेटेरिएट नहीं बनाया गया था लेकिन हमारे मुख्य मंत्री ने परसो कहा कि जींद से सारा काम चलेगा। इस बात के लिये मैं मुख्य मंत्री जी का अभिनन्दन करता हूँ और आशा करता हूँ कि भायद वे जींद को ही हरियाणा की कैपिटल बनाने पर विचार कर रहे हैं?

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल): हमारी राजधानी चण्डीगढ़ ही रहेगी।

चौधरी राम किशन: जब हरियाणा बज्जुद में आया था तो उस वक्त जींद को जिला बनाया गया था लेकिन आज वहां पर मिनी-सैक्रेटेरिएट नहीं बनाया गया। अब मेरे एक सवाल के जवाब में यह बताया गया है कि इस साल वहां पर मिनी-सैक्रेटेरिएट बन जायेगा। मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि वे अगले महीने ही उसका उद्घाटन करें। चेयरमैन साहब, हमारी जनता सरकार को वज्जुद में आए अभी दो साल हुए हैं लेकिन अभी से हमारे प्रांत के

ऊपर भगवान का प्रकोप है। कभी बाढ़ आ जाती है तो कभी ओले पड़ जाते हैं। पिछले साल बाढ़ के मौके पर हमारे मुख्य मंत्री जी ने बहुत समझदारी से काम लिया। वे खुद बाढ़ग्रस्त इलाकों में गये और सभी मंत्री तथा एम.एल.एज. ने भी वहां परी जाकर लोगों की सेवा की। इस बात को सब जानते हैं कि मुख्य मंत्री जी ने सभी सदस्यों को यह कहा था कि वे भी आकर श्रमदान के काम में भाग लें लेकिन विपक्ष की ओर से किसी भाई ने आकर काम नहीं किया। भाई पोहलू जोकि हमारे काम की सराहना करते हैं, हो सकता है ये कहीं पर गये हुए हों, इसलिये न आ सके हों। जिन गांवों को फलड ज्यादा आता था वहां पर मुख्य मंत्री जी ने रिंग बांध बांधने का अभियान चलाया। जींद जिले में बहुत से गांव हर साल बाढ़ की लपेट में आते थे लेकिन रिंग बांध बांधने की वजह से हमें बहुत फायदा हुआ है इसलिये सह भी बहुत सराहनीय कदम है। इसके आलवा बिजली के बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज से दो साल पहले बिजली बादलों में ही दिखा करती थी और जब कभी किसान को बिजली मिलती थी तो रात को ही मिलती थी। उन दिनों किसान जब अपने ट्रैक्टर पर पहुंचता था तो वहां पहुंचते ही बिजली गायब हो जाती थी लेकिन जब से हमारी जनता सरकार वजूद में आई है तब से किसान को 24 घंटे बिजली मिलती है। चेयरमैन साहब, मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस सरकार से पहले किसी सरकार ने भी देहात के लिए दिन खोल कर काम नहीं किया लेकिन मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि इसने इस बजट में 90 प्रतिशत पैसा देहात पर खर्च

करने के लिये रखा है। इसके अलावा सरकारने एक और भी बढ़िया काम किया है कि इसने बिजली की मीटर सिस्टम को खत्म करके फ्लैट रेट सिस्टम लागू कर दिया है पहले किसानो को बहुत परेशानी थी लेकिन अब इस सिस्टम के लागू होने से किसान खुश है। लेकिन मैं सरकार से एक प्रार्थना करूंगा कि वह इस सिस्टम को पंजाब और यूपी. पैट्रन पर इम्पलीमेंट करवाये। इसके अलावा चेयरमैन साहब, जब से यह सरकार आई है तब से अनाज की पैदावार बढ़ाने में भी हमने बहुत तरक्की की है। पहले जब हरियाणा बना था तो हमारी पैदावार कम थी और आज हालत यह है कि यहां पर इतना अनाज पैदा होता है कि हम दूसरी स्टेटों में भी अनाज भेजते हैं। हरियाणा का किसान बहुत मेहनती है लेकिन खेती में काम आने वाली जो चीजें हैं वे उसे बहुत महंगे भाव पर मिलती हैं। जितने भी गरीब किसान हैं, हरिजन हैं या बैकवर्ड क्लास के आदमी हैं, ये बेचारे हमें जैसे ही पिटते आए हैं। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह किसान को सस्ते भाव पर चीजें मुहैया करवाये। आज आप ट्रैक्टर को देख सकते हैं। इसकी कीमतें आप आकाश को छू रही हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि जिस भाव पर ट्रैक्टर पहले मिलते थे उसी भाव पर किसानो को ट्रैक्टर दिलाये जाये। इसके अलावा चेयरमैन साहब, पशु पालन की जहां तक इस बजट में चर्चा की गई है, इसको बारे में सरकार का बहुत ही सराहनीय पक्ष है। हरियाणा में मुराह भैंस और गायें, जिसकी अच्छी नसल का हरियाणा घर समझा जाता है, मुर्गी पालन, भेड़ पालन और मछली पालन का भी

बजट का जिक्र किया गया है। पहले लोग दर दर मारे मारे फिरते थे कि हमें कर्जा दिया जाये लेकिन उनको कर्जा नहीं मिलता था। आज मुख्य मंत्री जी ने सरकार की तरफ से यह एलान किया है कि चाहे आप गांव के अंदर इंडस्ट्री लगाओ, भेड़ पालन का काम करो, मुर्गी पालन का काम करो, हरेक को कर्जा मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि पशु पालन का महकमा जब से चौधरी भजन लाल जी के पास आया है, इस महकमे के अंदर बहुत ज्यादा काम हुआ है और जगह जगह पर स्टाकमैन सेंटर और वेटर्नरी डिस्पेंसरी खोलने का प्रबंध किया गया है यह भी एक सराहनीय पग है। इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आदमी के लिये अस्पताल जरूरी है, मैं यह समझता हूँ कि पशुधन की रक्षा के लिये हर गांव के अंदर फ़ैसिलिटीज देना बहुत ही जरूरी है अगर कोई आदमी बीमार हो जाये तो वह भाहर में जा सकता है, उसके जबान है वह बोलकर बता सकता है लेकिन अगर पशु बीमार हो जाये तो बोल नहीं सकता। उसको किसी चीज में रिकॉम में या गाड़ी में डालकर दूसरे किसी भाहर में ले जाया नहीं जा सकता। इसलिये मैं अपनी सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा धनराशि की उपलब्धि इस महकमे को कराई जाये ताकि गांवों में और भी ज्यादा स्टाकमैन सेंटर और पशुओं के अस्पताल खोले जा सकें। इसके अलावा चेयरमैन साहब, बजट के अंदर जहां तक सहकारिता यानी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का ताल्लुक है उसके बारे में भी चर्चा है। सरकार ने ब्याज की दर 14 प्रतिशत से घटाकर 11

प्रतिगत की है। इससे भी किसान को काफी राहत मिलेगी। पहले जो नोमीनेशन का सिस्टम था वह भी सरकार ने खत्म कर दिया है।

म्यूनिसिपल कमेटियों के जो इलैक्ट्रिकेशन होने वाले हैं, सरकारने यह भी एक नई प्रथा डाली है। डैमोक्रेसी को बहाल करने का सरकार का यह भी एक बहुत ही सराहनीय प्प है। चेयरमैन साहब, इसके अलावा बजट पंचायतों का भी जिक्र आया है। पहली सरकार कभी भी रिजर्व टाइम के अंदर पंचायतों के इलैक्ट्रिकेशन नहीं करवा सकी। वह घबराती थी कि भायद हमारे आदमी पंचायतों में इलैक्ट्रिकेशन होने की वजह से न आ पायेंगे लेकिन इस सरकार ने वजूद में आते ही पंचायतों के इलैक्ट्रिकेशन कराये और लगभग 54 लाख रुपये की धनराशि उन पंचायतों को दी जहां पर यूनिमस इलैक्ट्रिकेशन हुए थे यह भी सरकार का बहुत ही ज्यादा सराहनीय प्प है।

बजट के अंदर जंगलात का भी जिक्र किया गया है। चेयरमैन साहब, मैं यह कहता हूं कि जंगलात भी रेगिस्तान की तरफ उतनी ही जरूरी है जितनी कि और कोई चीज। किस वक्त वहां पर आंधी चलती है तो रेत उड़ करके गांव के गांव दबा लेती हैं जंगलात के महकमें ने इस रेत को रोकने के लिये जो काम किया है वह भी बहुत सराहनीय प्प है। इंडस्ट्री का भी बजट में जिक्र आया है मैं इस बारे में इंडस्ट्री मिनिस्टर डा. मंगल सैन जी को बधाई देना चाहता हूं। जैसे उनके टैलीफोन के खर्च का,

गाड़ी के खर्चे का और उनके बिलों का जिक्र आया, यह हो सकता है कि उन्होंने यह खर्चा केन्द्र की सरकार से काम करवाने के लिये खर्च किया हो, जिसकी वजह से करोड़ों रूपया केन्द्र से हरियाणा को मिला हो। (व्यवधान)

Mr. Chairman: No interruptions please.

चौधरी राम किान: चेयरमैन साहब, जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है, हो सकता है गलत भी हो, लेकिन मैं अपने ज्ञान की वजह से यह कहता हूँ कि 50-50 करोड़ रूपये की लागत का टैलीफोन का सामान बनाने का एक प्लांट जो पंचकूला में लगना था वह अभी तक नहीं लगा। मैं माननीय इंडस्ट्रीज मिनिस्टर डा. साहब से यह प्रार्थना करूंगा कि हमें यह सुनते हुए कि मामला विचारधीन है, दो साल हो गये हैं, लेकिन अभी तक नहीं लगा। क्यों आज तक वह प्लांट नहीं लग सका ? क्यों इतनी देर हुई है ? जहां तक इंडस्ट्रीज लगाने का ताल्लुक है, मुख्य मंत्री जी की यह मं ता और चेअर है कि यहां पर बेरोजगारी की समस्या छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगा कर दूर की जाये। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है कि इंडस्ट्रीज मिनिस्टर साहब केन्द्र के साथ बातचीत करके बड़े प्लांटों की मंजूदरी लाये जिसे लोने में वे अब तक कामयाब नहीं हुए। मेरी प्रार्थना यह है कि 'बड़े प्लांट हरियाणा में स्थापित करवाये जैसे कि जींद के अंदर, सफीदों के अंदर। इससे हजारों आदमियों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूँ कि जहां तक सड़कों का ताल्लुक है जब हरियाणा का गठन

हुआ उस वक्त केवल 1386 गांव ऐसे थे जो पक्की सड़कों से मिले हुए थे। उसके बाद 6 हजार किलोमीटर लम्बी सड़कें बनी हैं। जब से यह महकमा सरदार लछमन सिंह जी के पास आया है, इस महकमे ने काफी काम किया है। मुख्य मंत्री जी ने यह एलान भी किया है कि सन् 1982 में इलैक्शन से पहले कोई भी ऐसा गांव नहीं होगा जो पक्की सड़क से नहीं मिला हुआ होगा। जिस रफ्तार से ये सड़कें बनाई जा रही हैं उससे तमाम जिन्दगी भर सड़कों की समस्या दूर हो जायेगी। सरदार साहब ने जो यह सड़कें, बनाने का काम इतनी तेजी से भुरु करवाया है, मैं यह कहता हूँ कि इसके लिये वे भी मुबारकबाद के पात्र हैं। इसके अलावा हमारे मुख्य मंत्री चौधरी देवी लाल से पहले अगर कोई आदमी इस 82 प्रतिशत पिछड़े वर्ग यानी किसानों की तरफ ध्यान देता तो आज किसी को मांग रखने की जरूरत नहीं होती। आज यह जो विपक्ष के भाई कह कर बावैला मचाते हैं कि उनकी कांस्टीच्यूंसी में कोई काम नहीं हो रहा है। मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि 90 के 90 हलकों के बारे में मुख्य मंत्री जी के दिल में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। पिछले महीने की 22-23 तारीख को इनका दौरा 14-14 गांवों में था। मेरे जिले के उचाना हलके के अंदर उन्होंने कई पब्लिक मीटिंग एड्रेस की। वहां पर मैं। यह कहता हूँ कि यह इतना काम देकर आये हैं कि उतना दूसरी किसी कांस्टीच्यूंसी ने नहीं दिया होगा। इन भाईयो का यह कहना कि हमारे हल्के के अंदर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, भाोभा नहीं देता। मैं यह कहता हूँ कि जिस हल्के से वे आये

है वहां पर हमारे हल्के से ज्यादा काम हो रहा है। इसके अलावा चेयरमैन साहब, वाटर सप्लाई स्कीमों का भी बजट में जिक्र आया है। इस सरकार ने पीने के पानी की जो समस्या है वह दूर की है। जहां पर खराब पानी होगा वहां पर मीठा पानी दिया जायेगा। मैं यह कह सकता हूँ कि इतनी तेजी से इस डिपार्टमेंट का काम चला हुआ है कि भायद ही 1982 तक कोई ऐसा गांव या बैल्ट रहा जायेगा जहां पर वाटर सप्लाई की स्कीम न जा सके। सरकार साहब और इनका महकमा दोनों बधाई का पात्र है। जहां वाटर सप्लाई से पानी अवेलेबल होगा वहां अच्छे अच्छे पार्क और फव्वारे बनेंगे। ऐजुकेशन का भी बजट में जिक्र आया है। मैंने यह सुना है कि प्राइवेट कालेजिज को जो एड पहले 75 प्रतिशत दी जाती थी वह बढ़ाकर 84 प्रतिशत कर दी है। पहले यह एड 30 प्रतिशत होती थी, इसे बढ़ाकर पहले 75 प्रतिशत किया था और अब इसे 84 प्रतिशत कर दिया गया है। चेयरमैन साहब, देखिये कितना सराहनीय पग है। आपको पता है कि प्रांत के अंदर प्राइवेट कालेजिज की स्थिति कितनी खराब थी। सरकार ने इनको एड देकर बचा लिया। लेकिन मेरी सरकार से यह प्रार्थना है और सुझाव है कि जिस तरह से इन्होंने कालेजिज की एड बढ़ाई, इसी तरह से कुछ प्राइवेट हाई स्कूल भी देहात के अंदर हैं, खासकर फुलड के एरिया में इन स्कूलों की हालत इतनी खराब हो गई है कि वे मास्टर्स को तनख्वाह भी नहीं दे सकते। मेरे सफ़ीदों हल्के में भंभेवा गाँव है, बहुत बड़ा गाँव है, जितना सुन्दर उसके पास भवन है और काफी तादाद में लड़के वहाँ पर पढ़ते हैं लेकिन आज

वह गांव उन मास्टर्स की तनखाह देने में असमर्थ है इसलिये मैं अपनी सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि कोई भी स्कूल टेक ओवर करते वक्त मेरे हलके सफ़ीदों में खासकर भंभेवा जो किसानों का एक बहुत बड़ा गांव है, चारों तरु पानी आने की वजह से वहां के लोगों की हालत खराब हो गई है, अगर यह सरकार उस स्कूल को भी टेक ओवर करा ले, तो बड़ी कृपा होगी।

Mr. Chairman: Please wind up now. The time is over.

चौधरी राम किान: चेयरमैन साहब, मैं दो मिनट और लूंगा इसके अलावा चेयरमैन साहब, पिछड़े वर्ग के लोगों की पापुलेशन 20-22 प्रतिशत होते हुए भी इसके लिये सर्विसिज में 2 प्रतिशत आरक्षण रखा गया था। यह पिछड़े वर्ग पर एक बड़ा भारी धब्बा था। मुख्य मंत्री जी ने इस आरक्षण को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया है और इसकी चर्चा बजट में भी आई है इसके लिये मैं उसको अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि वे वाकई मुबारकबाद के पात्र हैं। यह रिजर्वेशन पिछड़े वर्ग के पापुलेशन को देखते हुए कम है। हो सकता है कि मुख्य मंत्री जी ने अपना मन बना रखा हो, अगर न बना रखा हो तो भी मेरी यह प्रार्थना है कि अगर इस आरक्षण को 5 प्रतिशत की बजाये 10 प्रतिशत कर दे तो उनकी बड़ी कृपा होगी। इसके अलावा चेयरमैन साहब, मैं मार्केट कमेटीयों का जिक्र करूंगा। मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि मार्केट कमेटी से जो आमदन होती

है, उसे उसी कांस्टीच्यूएंसी में, उसी हलके में, उसी जिले में लगा दिया जाये तो डिवैल्पमेंट के काफी काम हो सकेंगे और लोगों को राहत मिल सकेगी। इसके अलावा अंत में मैं मुख्य मंत्री जी से और वित्त मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि इस बजट के अंदर जो किसानों के ऊपर 10 प्रति ात आबियाना, 33 प्रति ात लैण्ड होल्डिंग टैक्स का जो प्रस्ताव है इस पर वे पुनर्विचार करके 82 प्रति ात देहात में रहने वाले गरीब किसानों को अगर किसी तरीके से बचाया जा सके तो उनकी बड़ी भारी कृपा होगी और इसकी बजाये वे जो बड़े बड़े सिनेमा वाले हैं, जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर यह टैक्स लगा दिया जाये तो कोई बुरी बात नहीं होगी। चेयरमैन साहब, मैं बजट का समर्थन करते हुए अपनी जगह लेता हूँ। धन्यवाद।

श्री भाम ार सिंह (नरवाना): चेयरमैन साहब, मैं 1979-80 के बजट के बारे में जो वित्त मंत्री जी ने विधानसभा में पे ा किया है और जिसमें नान प्लान के लिये 257 करोड़ रुपये स्कीम के लिये 227 करोड़ रुपये के खर्चे का प्रावधान किया गया है उसके बारे में अपने विचार पे ा करना चाहता हूँ। चेयरमैन साहब, 37 करोड़ रुपये के घाटे का यह बजट जिसमें से 14 करोड़ रुपये भारत सरकार से ग्रांट के रूप में हरियाणा सरकार को मिलेगा और 10 करोड़ रुपये के लगभग टैक्सों का प्रावधान इस बजट के किया है इसके बावजूद भी 13 करोड़ रुपये का घाटा इस बजट में खुला छोड़ दिया गया है। चेयरमैन साहब, इस

13 करोड़ रुपये के घाटे को कवर करने के लिये वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तावों में यह ठीक कहा है कि फरीदाबाद और दिल्ली के आसपास जो हरियाणा के इंडस्ट्रियल टाउन्ज है, वहां के जो कारखानेदार हैं उन्होंने अपने दफ्तर दिल्ली में बनाए हुए हैं इसलिये करोड़ों का टैक्स घाटा हरियाणा को होता है। हर साल टैक्स की भावना में, एक्साइज की भावना में या और किसी रूप में। यह बात ठीक सोची जा रही है कि सरकार उनके ऊपर एक टैक्स इस बात का लगाये कि जो माल वहां पर बन कर हरियाणा से बाहर जायेगा उसके ऊपर उन्हें सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि अच्छा होता अगर वह इसी बजट प्रस्तावों में उस टैक्स को ले करके आते ताकि हाउस को उस पर बहस करने का मौका मिलता। चेयरमैन साहब, यह भी सम्भव हो सकता कि जनता पार्टी की सरकार भावना उस बीच में उन कारखानेदारों के दबाव में आकर बाद में हाउस से बाहर प्रैस में यह कह दे कि वह टैक्स हम नहीं लगा रहे (गोर)।

वित्त मंत्री (श्री मूल चंद जैन): चेयरमैन साहब, श्री भाम गोर सिंह जी को गलतफहमी है वह बिल हम इसी सदन में ला रहे हैं।

श्री भाम गोर सिंह: जैन साहब, गलतफहमी की बात नहीं है। इस बजट प्रस्तावों में इस टैक्स को इसी सदन में लाने का कोई जिक्र नहीं है। चेयरमैन साहब, इस हाउस से बाहर मुख्य

मंत्री जी और दूसरे मंत्रियों द्वारा यह कहा गया है कि सरे हरियाणा का जो बजट है इसका 80 या 90 प्रतिशत जो भाग है वह देहात की तरक्की पर और खेतीबाड़ी परया कृशि पर खर्च करने जा रहे है। इन्होंने इस बात का देहात मे प्रचार किया है। चेयरमैन साहब, अगर आप सही तौर से देखे तो मैं यह कहूंगा कि यह बात बिल्कुल गलत है और यह बात सही नहीं है। इस बजट मे 171 करोड़ रूपया, जो सारे बजट का 70 या 75 परसेंट बनता है वह कृशि, सिंचाई और बिजली के लिये रखा गया है। चेयरमैन साहब, अगर आप उन सारे आंकड़ों को अलाहिदा अलाहिदा देखे तो कृशि जो हे या खेतीबाड़ी जो हे और उससे संबंधित जो सैक्टर है जिसके अंदर पंचायत कम्युनिटी और प्राईवेट सैक्टर भी शामिल है उनके लिये सिर्फ 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है जोकि इस सरे बजट का 11 परसेंट बनता है। अगर हमारी वित्त मंत्री जी बा बात का दावा करें कि जो सिंचाई तथा बिजली की मद मे 60-62 करोड़ रूपये रखे गये है वह कृशि और खेतीबाड़ी के लिये है तो यह बात सही नहीं है। अगर आप आंकड़े देखे तो इन 60-62 करोड़ रूपये मे से केवल 12 करोड़ रूपये का कृशि के लिये या खेतीबाड़ी के लिये तथा किसानों को गांवो मे बिजली की एक्सटेंशन के लिये प्रावधान है बाकी इसका 90 परसेंट भाग इंडस्ट्रीज और भाहरों के लिये बिजली उत्पादन पर खर्च होना है। इस प्रकार से सिंचाई के आंकड़े 60 करोड़ के करीब है। चेयरमैन साहब, यह जो एस.वाई.एल. स्कीम को पूरा करने के लिये पैसा रखा गया है इससे हरियाणा के लोगो को पानी मिलने वाला नहीं

और न ही उनको कोई लाभ होने वाला है। इसी से जुड़ती हुई बात एक और है कि जब तक पंजाब के भाग में एस.वाई.एल. कैनल का हिस्सा बन करके तैयार नहीं हो जाता तब तक हरियाणा में उसका पानी नहीं आ सकता। चेयरमैन साहब, मैं तो कहूंगा कि यह सारे का सारा डैड मनी है हतससे हरियाणा के किसानों को कोई लाभ नहीं पहुंचना है। इसके साथ ही इस बजट में जिन दूसरी बातों का जिक्र किया गया है उनके बारे में मैं तो यह कहूंगा कि खेती को प्राथमिकता देने की बात हो बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है। चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी से यह नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि खेती को जो प्राथमिकता देने की बात है वह बहुत सी बातों से जुड़ी हुई है जैसे किसानों को उनकी जिन्स के पूरे भाव मिलने की है। सरकार ने इस बजट में सबसिडी के लिये चाहे वह फर्टिलाइजर, बीज और दूसरी चीजों पर है, के लिये जो पैसा रखा गया है उसमें किसान को इतना फायदा होने वाला नहीं है जब तक कि उसको उसकी पलज का पूरा भाव न मिले। इस स्कीमों से किसानों को कोई लाभ होने वाला नहीं है इससे किसानों की हालत को सुधारा नहीं जा सकता है। उदाहरण के तौर पर हरियाणा में किसान को एक क्विंटल गेहूँ की पैदावार पर 120 रुपये के करीब खर्च करना पड़ता है और उनको एक क्विंटल गेहूँ का भाव 110 रुपये भी नहीं मिलता है। इस प्रकार मैं चाहे गन्ने की बात कहूँ, गुड़ की बात कहूँ, चाहे कपास की बात कहूँ, चाहे बाजरा की बात कहूँ, सरसों की बात कहूँ और चाहे आलूओं की

बात कहूं, किसान को जिन्स का जितना भाव मार्केट में मिलता है उससे दोगुना, अढ़ाई गुना या तीन गुना खर्चा एक क्विंटल पैदा करने के लिये खर्च करना पड़ता है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि किसान जितना ज्यादा अनाज मार्केट में लेकर जाता है उतना ही टोटा अपने कंधों पर लेकर आता है, उसको फायदे की बजाये नुकसान उठाना पड़ता है। इस सिस्टम से किसान के सिर पा लाखों करोड़ों रूपया, मिनी बैंक्स और दूसरे बैंकों के जरिए कर्ज के रूप में चढ़ता जा रहा है। अगर खेत की पैदावार की नीति इसी तरह चलती रही तो वे दिन दूर नहीं जब हरियाणा के प्रत्येक किसान की सारी की सारी भूमि, जितनी भी जमीन किसान के पास है वह बिक जायेगी और वह अगले चार पांच सालों में इस जमीन का मालिक नहीं रहेगा। किसान अपनी मलकीयत खो बैठेगा। चेयरमैन साहब, मैं आपके द्वारा सरकार से कहना चाहता हूँ कि किसान का पेट महज प्रचार करने से नहीं भर सकता। बजट के अंदर जो आंकड़े दिये गये हैं, वह इस तरह की जादूगरी है, एक जगलरी है, इनसे किसान का पेट नहीं भर सकता अगर सरकार किसान की हितैशी है तो सरकार को यह फैसला करना होगा कि किसान को नुकसान न होने दिया जायेगा। उसकी प्रोड्यूस उचित दामों पर बिकनी चाहिए। यह नीति जिससे किसान को करोड़ों रूपये का नुकसान होता है, बदलनी चाहिए।

चेयरमैन साहब, इसके साथ ही साथ मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि आज किसान की दोहरी लूट होती है। एक

तरफ तो किसान को जिन्स का भाव पूरा नहीं मिलता और दूसरी तरफ उसके इस्तेमाल की चीजें महंगी हैं। जिसके कारण उसे पैदावार करने के लिये ज्यादा खर्च करना पड़ता है, चाहे मीनरी है, चाहे डीजल है, चाहे खाद है, चाहे वह बीज है, चाहे सीमेंट है, चाहे ईंट है, चाहे लोहा है। हर चीज की कीमत पिछले दो सालों से निरंतर बढ़ती जा रही है और खेतीबाड़ी करने के लिये किसान को बहुत ज्यादा कीमत देनी पड़ती है। चेयरमैन साहब, कई आईटम्ज ऐसी हैं जो मार्किट में मिलती नहीं हैं, जैसे डीजल, सीमेंट और ईंटें। ये चीजें आज मार्किट में उपलब्ध नहीं हैं और किसान को ब्लैक में खरीदनी पड़ रही है। यही खाद की पोजीशन है। चेयरमैन साहब, कोऑपरेटिव सोसायटीज द्वारा जो खाद किसान को दी जाती है, मैं इसका जिक्र करना चाहता हूँ। खाद पर जो सबसिडी दी जाती है, हरियाणा में खाद की सबसिडी के नाम पर बड़ा भारी स्कैंडल है। सरकार ने किसान को सबसिडी देने के लिये जो रकम रखी है, इसके बारे में अगर मैं यह कहूँ कि इस में से एक भी पैसा किसान को नहीं मिलता तो इसमें कोई झूठ नहीं है। मैं उदाहरण देकर सदन को बताना चाहता हूँ कि खाद तीन किस्म की है। जिन खादों पर सरकार ने सबसिडी दी है वह एन.पी. खाद जिस पर प्रति कट्टा 13 रुपये सबसिडी है, एन.ए. पी. पर 17 रुपये और हीदा खाद पर 12 रुपये है। यूरिया खाद पर कोई सबसिडी नहीं है। आप सब जानते हैं कि हैफड खाद बांटने का मेन सोर्स है और इसकी ब्रांचें सब जगह हैं। किसी खास एरिया में या सब डिस्ट्रिक्ट में मिनी बैंक्स भी खाद देते हैं।

जो लोग यूरिया खाद ले जाते हैं वे अपने रिकार्ड में हेराफेरी करे यूरिया के कट्टो पर हीरा खाद या एन.ए.पी. खाद का नाम लिख देते हैं और सारी सबसिडी उनकी जेब में चली जाती है और बाद में सबसिडी वाली खाद को पंजाब में जाकर बेच देते हैं जहां पर उकसा रेट हरियाणा के मुकाबले में ज्यादा है और तकरीबन 15-20 रुपये फी कट्टा ब्लैक में बिकती है। हरियाणा के किसान को सबसिडी का एं पैसा भी नहीं मिलता। चेरमैन साहब, मैंने ग्रिवेंसिज कमेटी की मीटिंग में अलग अलग जगहों का नाम ले कर बताया था, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी बात पर अब तक कोई ऐक्शन नहीं हुआ। चेरमैन साहब, मैं आपकी मारफत सरकार से कहना चाहता हूं कि फौरन ऐक्शन लिया जाये ताकि किसानों को सबसिडी का फायदा हो सके चेरमैन साहब, मिनी बैंकों की मारफत किसानों को कर्ज दिये जाते हैं जिसका प्रचार सरकार एजेंसियों से किया जाता है। मिनी बैंक में बड़ा भारी स्कैंडल मौजूद है जिसका पता मिनिस्टर कंसर्न्ड को भी है और सरकार के नोटिस में भी है और हरियाणा में लाखों करोड़ों रुपये की हेराफेरी छोटे छोटे किसानों के साथ हो रही है। जिस आदमी ने मिनी बैंक से कर्जा नहीं लिया है उसका नाम रजिस्टर में दर्ज है, परनोट पर अगूँठा लगा हुआ है.....

श्री मूल चंद जैन: आप तो कांग्रेस के जमाने की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री भाम ार सिंह: नही, मैं नही जनतार गवर्नमेंट के जमाने की बात कर रहा हूँ।

श्री सभापति: आपका टाईम हो गया है, आप वाइंड अप करें।

श्री भाम ार सिंह: अच्छा जी। जिन लोगो ने कर्जा नही लिया है उनके खिलाफ आर्बिट्रे ान ने डिग्रियां दे दी है, सैंकड़ों आदमी परे ान हो रहे है, करोड़ों रूपयों की हेराफेरी हुई है। चेयरमैन साहब, जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, किसान की बार बार लूट और पिटाई हो रही है। सबसिडी भी नही मिल रही और उसको उसकी जिनस के भाव भी पूरे नही मिल रहे है। चेयरमैन साहब, हरियाणा का किसान एक नै ानल मेन स्ट्रीम है, इसको जनता पार्टी के राज मे काटा जा रहा है और इसके दूसरी तरफ सरकार ने इस बात का प्रचार माउंट किया है कि सरकार किसान के लिये सब कुछ कर रही है।

चौधरी देवी लाल: यही बात तो आपको दूखती है ?
(व्यवधान)

श्री भाम ार सिंह: किसान के लिये सरकार ने कुछ नही किया और किसान दूसरे लोगों की आंखों मे कांटे की तरह चुभता है।

चौधरी लाल सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर । मैं अपने दोस्त को बताना चाहता हूँ जो कुछ जनता सरकार ने

जमींदारों के लिये किया है भायद ही किसी दूसरी सरकार ने किया हो। पिछली सरकार ने किसानों के ऊपर टैक्स लगाया था लेकिन जनता सरकार ने आते ही वह टैक्स मुआफ कर दिया।

श्री भाम ेर सिंह: चेयरमैन साहब, मैं कह रहा था कि सामाजिक तौर पर किसान एक प्रिविलेज्ड सैव क्लास है लेकिन यह सैव क्लास सामाजिक की मेन स्ट्रीम से कटआफ हो गया है।

श्री सभापति: अब आप वाइंड अप करें।

श्री भाम ेर सिंह: चेयरमैन साहब, बजट में इस बात का जिक्र किया गया है कि हरियाणा की जनता आर्थिक और सामाजिक न्याय से पीड़ित है और सहायता के लिये पुकार रही है। चेयरमैन साहब, वित्त मंत्री साहब श्री मूल चंद जैन को मैं जाती तौर पर जानता हूँ, ये बड़े प्रोग्रेसिव और सामाजवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं। चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से इनसे एक सवाल करना चाहता हूँ। सरकार ने लिखा है कि जनता सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिये पुकार रही है, क्या इससे यह जाहिर नहीं होता कि जनता, पार्टी को पुकार रही है कि हमें न्याय दो। अगर जनता पार्टी को पुकार रही है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकारने हरियाणा के लोगों पर बस का किराया बढ़ा दिया है, उनको न्याय नहीं दे सकी। आज हरियाणा की बस सर्विस हिन्दुस्तान में तो क्या, सारी दुनियां से वर्स्ट है, मैं यह बात जाति तजुर्बे के साथ कह रहा हूँ, मैं बसों में सफर करता हूँ। छोटे से

छोटे डिस्ट्रिक्ट में भी बस अपने डैस्टिनेशन पर नहीं पहुंचती, पहुंचने से पहले कम से कम दो तीन बार ब्रेक डाउन होता है। तब कहीं जाकर पहुंचती है और यात्रियों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इतनी रद्दी और इन एफिफिएंट बस सर्विस हरियाणा की है जिसका तोफा साढ़े 12 परसेंट बस भाड़े में वृद्धि करके दिया है। छोटे तबके के लोग बसों में सफर करते हैं, उनको यह तोहफा दिया है। हलवाई लोग जो सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक भट्ठी के सामने तपते हैं, उनकी 40 हजार से ज्यादा सेल पर सरकार ने टैक्स लगा दिया है। क्या हरियाणा सरकार यह समझती है कि हलवाई बहुत अमीर तबका है? चेयरमैन साहब, इन्होंने बजट प्रोजेक्ट में करियाना का काम करने वाले हमारे जो व्यापारी हैं उनकी टैक्स की लिमिट 40 हजार रुपये से रोज करके 1 लाख रुपये कर दी है। मैं इससे गुरेज नहीं करता लेकिन दुख की बात यह है कि उनसे भी ज्यादा गरीब और पीड़ित जो वर्ग है, हलवाई, चाय या इसी तरह का दूसरा करने वालों का, उन पर बहुत ज्यादा टैक्स लगायेंगे।

श्री मूल चंद जैन: चेयरमैन साहब, इनसे यह पूछा जाये कि वह टैक्स हलवाई पर है या कंज्यूमर्ज पर है ?

श्री भामोर सिंह: चेयरमैन साहब, कहने को तो टैक्स कंज्यूमर्ज के ऊपर है लेकिन असल बात यह है कि दुकानदार को इससे बिजनेस में बहुत बड़ा सैट बैक होता है। इस पैसे में

मार्किट मे कम्पीटी इन इतना ज्यादा है कि उसको टैक्स मिलने का सवाल ही नहीं है।

चेयरमैन साहब, रहन और बै की जो रजिस्ट्रिया होती भी इन्होंने 25 परसेंट टैक्स लगाया है। चेयरमैन साहब, रहन और बै आदि की रजिस्ट्रियां चूंकि ज्यादातर छोटे छोटे किसान और दूसरे लोग कराते है इसलिये यह टैक्स बढ़ाया जाना उनके साथ अन्याय है। चेयरमैन साहब, यही नहीं, सीमेंट जैसी आम इस्तेमाल की चीजों के ऊपर भी, जिसका कंट्रोल टैक्स लगाएंगे। इससे हरियाणा मे मकान आदि बनाने की जो ऐक्टिविटी है उसको बड़ी भारी सैट बैक पहुंचेगा।

चेयरमैन साहब, खेती बाड़ी का जहां तक संबंध है, उसके बारे मे अर्ज यह है कि सवा छः एकड़ से फालतू जो जमीन है उसके ऊपर इन्होंने सवा तेतीस परसेंट टैक्स लगाया है। यह भी बड़ी ज्यादाती वाली बात है। (विघ्न) किसी प्रकार की जस्टिफिके इन इसकी नहीं है।

श्री सभापति: अब आप वाईड अप कीजिए।

श्री भाम ोर सिंह: चेयरमैन साहब, मैं स्पीकर साहब से मिल था। उन्होंने यह कहा था कि मुझे ज्यादा टाईम दे दिया जायेगा क्योंकि अपोजि इन के बाकी साथियों को ज्यादा टाईम नहीं मिला है। (विघ्न)

श्री सभापति: आपको काफी टाईम मिल रहा है। अब आप कृपया वाईड अप कीजिए।

श्री भाम ोर सिंह: चेयरमैन साहब, नहरी पानी के ऊपर भी जो टैक्स लगा है उसकी भी कोई जस्टिफिके ोन नहीं है। जब हर सरकार पंजाब से पानी लेकर नहीं आती है और हरियाणा के किसान को पूरा पानी नहीं मिलता है तब तक आबियाना बढ़ाने का कोई सवाल ही नहीं है।

सभापति जी, मैं एक बात ओर कह कर अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा। आज हरियाणा मे ला एंड आर्डर की पोजी ोन बड़ी खराब है। मैं असैंबली मे कल दिये गये एक प्र ोन के उत्तर मे रैफर करना चाहूंगा । चेयरमैन साहब, इसमे 1-4-78 से 31-1-79 तक की और 1-4-76 से 31-1-77 तक की ला एंड आर्डर की पोजी ोन का मुकाबला किया गया है। कत्ल जो है वे 147 पहले पीरियड मे थे और अब 247 हुए है। कहने का मतलब है कि 100 ज्यादा हुए है। इसी तरह से इरादा कत्ल के 103, रायटिंग के 130 रौबरी के 14, डकैती के 30, चोरियों के 1600 और किडनैपिंग के 80 केसिज ज्यादा है। इसी तरह से हरिजनों के ऊपर अत्याचारों की फिगर जो इन्होंने असैंबली क्वै चन मे जवाब मे एक साल की दी है वह 63 है। इनमें से तीन केसिज मे कत्ल हुए, 10 मे रेप हुए, 4 आर्सन के है, 1 ग्रिवियस हर्ट का है, 18 असौल्ट के है, किडनैपिंग के 9 है, इव टीजिंग के 19 है और अनटचेबिलिटी के 4 है। यही नहीं 11 आदमी और भी पुलिस के

अत्याचार के िकार हुए है । 7 आदमी तो पुलिस की गोलियों से मारे गये और 4 आदमी जख्मी हुए। इसके अलावा चैयरमेन साहब, मैं तीन चार बातों का और जिक्र करना चाहता हूं। अम्बाला भाहर के हरि मंदिर के पास रहने वाली एक विधवा श्रीमती भान्ती देवी के घर पर 4 मार्च 1979 को डाका पड़ा, उसका रेप किया गया और कत्ल किया गया। लेकिन आज तक मुलजिम का पता नहीं लगा। इसी तरह से अलीपुर गांव, जो उचाना मे है, मे भी 17-2-79 को डाका पड़ा। 40 हजार रूपये का धन गया लेकिन मुजलिम पकड़े जाने के के बाद भी पुलिस ने छोड़ दिये। घरौंडा मे भी पिछले महीने के आखिर मे एक डाका पड़ा था लेकिन आज तक उसमे भी कोई मुलजिम गिरफतार नहीं हुआ। इसी प्रकार बेरी मे, आपने अखबार मे पढ़ा होगा, हरिजनों पर गैर हरिजनों ने किस तरह हमले किये। ईंटो और हथियारो का इस्तेमाल किया गया। इस तरह के हमले निहायत भार्मनाक है और ये चेतावनी देते है कि इनका प्रबंध बहुत जल्दी से जल्दी होना चाहिए। 15 मार्च को कुरुक्षेत्र के एक ही इंसिडेंस मे 6 आदमियो का कत्ल कर दियसाग या जिसमे एक बाप और उसके तीन लड़के भी भामिल थे। 16 मार्च को डाक्टरों ने काले बिल्ले लगा कर प्रोटैक्ट किया और कहा कि उनके बीवी बच्चो की जान सुरक्षित नहीं है। कालनवाली, किलोई, फरीदाबाद, खेड़ी कलां, मदीना और झज्जर मे डाक्टरों के ऊपर हमले हुए । नोलथा मे दो नन्हें बच्चों का कत्ल किया गया । पुलिस मे केस दर्ज हुआ है। लेकिन पुलिस ने असली मुजलिम को कुछ नहीं कहा लेकिन दूसरे लोगो पर रूपया

ऐंठने के लिये जुल्म करने भारु कर दिये। मेरे पास सारे गांव के लोगों, पंचों और सरपंचों की दरखास्त मौजूद है। इसमें कहा गया है कि पुलिस इस घोटाले में भागिल है। जगाधरी में गांव मौथूवाला के बारु राम हरिजन को एक बिस्वेदार ने मार दिया लेकिन मुलजिम का पता होने के बावजूद भी आज तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। पानीपत के पास चार मजारों को न केवल बेदखल कर दिया गया बल्कि उनका कत्ल कर दिया गया। यह पुलिस की भाह से हुआ। इस बाम का सबूत मौजूद है कि इसके अलावा चेयरमैन साहब, आपने देखा कि पिछले दो साल में कितनी बार ट्रैफिक जाम हुआ। जरा सी बात के ऊपर बस और गाड़ियां सड़क के ऊपर खड़ी कर दी जाती है। ऐसा लगता है कि सरकार का किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है। चेयरमैन साहब, हरिजनो पर कारखाने के मजदूरों पर, विद्यार्थियों पर और सरकारी कर्मचारियों पर दफा 144 लगा करके अत्याचार किये जा रहे हैं। फरीदाबाद और दूसरी जगहों में कारखानेदारों से मिल कर हजारों की संख्या में मजदूरों की छांटी की गई। आज बड़ा रिप्रैशन का वातारण सारे हरियाणा के अंदर बना हुआ है।

Mr. Chairman: Please sit down. Your time is over.
Chaudhri Shiv Ram Verma.

श्री भामोर सिंह: चेयरमैन साहब, मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के बारे में भी केवल एक बात कहना चाहता हूँ।

Mr. Chairman: No please. Your time is over. Please take your seat now.

चौधरी िव राम वर्मा (नीलोखेड़ी): चेयरमैन साहब, दो दिन से 1979-80 के बजट प्रस्तावों पर चर्चा चल रही है। इसके बारे में मैं भी थोड़ा सा कहना चाहूंगा। विरोधी पक्ष के बारे में हमारे साथी यह समझते हैं कि वह भी सरकार की तारीफ करे, लेकिन मैं समझता हूँ कि यह गलत बात है। हम क्यों इनकी राह देखे कि ये हमारी तारीफ करे। हमें तो अपना काम अपने आप देखना चाहिए। अगर ठीक है तो ठीक है लेकिन अगर किसी काम को कोई गलत बताता है तो उसे हमें सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए।

वाक आउट

श्री भाम ाम सिंह: चेयरमैन साहब, स्पीकर साहब से हमारा यह फैसला हुआ था कि चूंकि हम पहले दिनों में नहीं बोले हैं इसलिये हमारे साथियों को बोलने का ज्यादा मौका दिया जायेगा। अगर इस तरह से हमें पूरी बात भी नहीं कहने दी जाती तो as a protest we walk out of the House.

(At this stage Sarvshri Shamsheer Singh, Jagjit Singh Pohloo, Dalip Singh Surender Singh and Narain Singh staged a walk out.)

वर्ष 1979-80 के बजट पर आम चर्चा (पुनरारम्भ)

चौधरी भाव राम वर्मा: चेयरमैन साहब, सात तारीख को, जिस दिन वित्त मंत्री जी का बजट भाषण हुआ था, सदन में अपने ही सदस्यों की ओर से ऐसा वातावरण पैदा हो गया था, जो हमें भागे भागे नहीं देता था, परंतु उन सदस्यों के बारे में मैं यह समझता हूँ कि वे यह कह सकते हैं कि वे नए थे, जो 1950 में थे क्योंकि नौजवान थे, लेकिन हमारे वित्त मंत्री जी ने जिस ढंग से अपनी बात कही और उन नौजवान साथियों को कुलक कह कर पुकारा वह भी कोई अच्छी बात नहीं थी। वे तो पुराने आदमी हैं, पुराने लैजिसलेटर हैं और उमर में भी काफी बड़े हैं। इन्हें तो संभल कर बात करनी चाहिए थी। कुलक किस को कहते हैं मैं यह नहीं समझ पाया हूँ। उनको इस भाब्द के बारे में स्पष्टीकरण करना चाहिए कि वे इस को कहां से लाये हैं ? कुलकर क्या होते हैं और इस समय हरियाणा में कितने कुलक हैं। वे इस समय इस स्थिति में हैं कि हर प्रकार की जानकारी प्राप्त करके बता सकते हैं। वे चिड़ कर कर रहे हैं मुझे एंटी किसान कहा गया है इसलिये मैंने कुलक कहा है तो मैं इसको ठीक नहीं समझता । वे आज किसान को कुलक कहते हैं ? यदि उन पर एंटी किसान का दोष लगाया गया है तो वे ये भाब्द कह कर साबित करना चाहते हैं कि वे एंटी किसान हैं। किसानों के बारे में ऐसा कहना कोई अच्छी बात नहीं है आज तक सब से ज्यादा किसान को ही रगड़ा गया है और किसान ही आज सब से गरीब हालत में हैं। जब जमीन पर सीलिंग हो गई कि कोई भी किसान 18 एकड़ से ज्यादा नहीं रख सकता है तो फिर वह बड़ा जमींदार कैसे रह गया? कानून के

अंदर उसकी जमीन आ गई है और वह आज उसके पास से नहीं निकली है तो कल को निकलने वाली है, उसको बड़ा जमींदार कैसे कह सकते हैं? इसलिये वित्त मंत्री जी की भावना किसानों के प्रति ठीक होनी चाहिए उनको किसानों की स्थिति को समझना चाहिए। किसानों की स्थिति को समझे बिना हरियाणा का भला नहीं हो सकता। हरियाणा में 70 परसेंट से अधिक लोग कृषि पर गुजारा करते हैं। कई किसान भाई तो ऐसे हैं जिनके पास एक एकड़ जमीन है। कुछ लोग जो 18 और 20 एकड़ जमीन के मालिक हैं, वे भी बड़े जमींदार नहीं हो सकते। अगर हम किसान का भला करते हैं तो सारे हरियाणा का भला करते हैं। किसान की जेब में पैसा जायेगा तो सारे वर्ग के लोगो कमे बंट जायेगा अगर किसान के पास पैसा नहीं है तो सारा हरियाणा गरीब रहेगा। हम चाहे कितनी ही योजनायें बना लें किसान का भला होने वाला नहीं है किसान की हालत को समझना बहुत आवश्यक है। मैं यह बात पहले भी कहा करता था और यह बात सब के सामने भी है कि सरकार दो बातें किसानों के लिये कर दे तो उनका भला हो सकता है एक तो उनके खेत पानी से भले नहीं और दूसरे पानी बिना खेत सूखें नहीं। ये दोनों बातें हो जाये तो किसान इतना अनाज पैदा कर देगा कि बाहर के देशों से मंगाने की बजाए बाहर भेजना शुरू कर देंगे मैं पहले भी यह बात कहता रहा हूँ लेकिन पिछले कई साल में मेरी बात सुनी नहीं गई। पहले इन दोनों चीजों का प्रबंध करना तो बड़ा भारी प्रोग्राम बताया जाता रहा है पिछली सरकार इस बारे में कहती रही थी कि इसको कैसे

किया जा सकता है, यह कुदरत की बात है कि बाढ़ आ गई या सुखा पड़ गया लेकिन मैं कहता रहा हूँ कि सरकार करे तो काफी कुछ किया जा सकता है मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि अब सरकार ने काफी योजनाबद्ध तरीके से काम करना आरम्भ किया है। बाढ़ नियंत्रण का काम पिछली सरकार ने उतना तीस साल में नहीं किया जितना जनता सरकार ने पिछले दो सालों में किया है। इस तरह से काम करने पर सरकार की नियत का पता लगता है कि सरकार इस दिशा में प्रयत्न कर रही है कि बाढ़ न आये। अगर फिर भी बाढ़ आती है तो बेबसी की बात है। इसका पूरा प्रबंध करने में समय तो लगेगा ही परंतु रास्ता ठीक पकड़ा है।

इसके साथ साथ मैं यह भी कहूँगा कि जहां पर बाढ़ आ गई थी वहां पर बाढ़ को रोकने के लिये तुरंत कदम उठाये गये। वहां लोगों को उचित सहायता भी सरकार की तरफ से भीर्घता से दी गई। जिसकी सहायता इस सरकार के टाईम पर दी गई है इतनी पहले कभी नहीं दी गई। इस बात को सभी मानेंगे चाहे वे विरोधी पक्ष के भाई हैं या सरकार के पक्ष के हैं। मैं यह बात पहले भी कहता रहा हूँ कि जिस तरह से पहले सरकार प्रबंध करती थी उस तरह से लोग का भला नहीं हो सकता था। हर साल बाढ़ आ जाती थी और छः महीने के पचात् चार चार धड़ी अनाज बांट दिया जाता और चालीस रूपये बाढ़ के नाम से मकान मुरम्मत के लिये दे दिये जाते थे। इस तरह से हर साल सरकार का काफी रूपया खर्च हो जाता था। जनता सरकार के आने के

पचात् तुरींत् बाढ के पानी को निकालने का प्रबंध किया गया ओर जो जमीन बाढ के कारण खराब हो गई थी उसको तुरंत ठीक करवाया गयाचाहे वह ट्रैक्टर भेज कर किया या किसी अन्य तरीके से किया । सारी जमीन को ठीक करके बीजाई की। यह इससे साफ जाहिर है कि बाढ आने के बाद भी हरियाणा मे पैदावार बढ़ी है क्योंकि सरकार ने भीघ्रता से कदम उठाये औरजमीन को ठीक करवाया ताकि लोग बीजाई समय पर कर सकें ।

चेयरमैन साहब, बाढ नियंत्रण की जितनी परियोजनायें जनता सरकार के आने के बाद अगले वर्षा के लिये बनाई गबई है वह भी किसी से छुपी हुई नहीं है । मैंने पहले वाली सरकार के समय पर यह कहा था कि सारे हरियाणा के बारे मे बाढ नियंत्रण का एक बार प्रोग्राम बना ले फिर आहिस्ता आहिस्ता काम करते चले जाये लेकिन उस सरकार ने इस बात पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया । जनता सरकारने 138 करोड़ रूप्ये की योजना बनाई है उसमे अगले वर्षा के लिये चालीस करोड़ की योजना बनाई है । इस बारे मे मैं निवेदन करूंगा कि इस बारे मे चौकस रहना आवयक है क्योंकि इसमे से कुछ रूप्या इधर उधर हो सकता है, गलत जगह पर ड्रेने बनाई जा सकती है । कहीं पर ऊंची जमीन से भी ड्रेन निकाली जा सकती है, इस किस्म की हेराफेरी हो सकती हैं पिछले दिनों एक क्वैचन के जवाब मे सिंचाई मंत्री जी ने कहा था कि रेअर केसिज मे ऊंची जगह से भी ड्रेन निकाली जा

सकती है। इस बारे में मेरा निवेदन है कि सरकार एक असूल बना ले कि जहां से पानी का कुदरती बहाव है वहां से ही ड्रेन को निकाला जाये चाहे किसी की कितनी ही भूमि आये। ऐसा करने से कोई झगड़ा नहीं हो सकता। अगर ऐसा नहीं किया गया तो जो लोग एजेंट बने फिरते हैं, कुछ वकील भी हैं, वे दूसरे लोगों को उकसा कर कहेंगे कि मैं इस ड्रेन को वहां की बजाए यहां से निकलवा दूंगा। इस तरह से लोगों के साथ हेराफेरी करेंगे। इसलिये इन ठेकेदारों को खत्म करने के लिये एक असूल बना ले कि जहां से पानी का बहाव हो, वहां से ही ड्रेन बनाई जाये चाहे कोई कितना ही एतराज करे। ऐसा करने से पानी निकालने की समस्या हल हो जायेगी और ड्रेन भी खराब नहीं होगी। दूसरे भ्रष्टाचार भी खत्म हो जायेगा। इस तरह से अगर बाढ़ नियंत्रण का काम सरकार ने किया जात उसके लिये सभी लोग सरकार को बधाई देंगे।

चेयरमैन साहब, ओलावृष्टि से भी किसानों को बहुत हानि हुई है उसके लिये भी सरकार भीघ्रता से सहायता के लिये आई है। मैंने सदन में मांग की थी कि सरकार को उन्हें जल्दी से जल्दी मुआवजा देने का प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि किसानों पर पहले से जो कर्जा है जब तक वह वापिस नहीं किया जायेगा तब तक आगे कर्जा नहीं मिलेगा इसलिये जितनी जल्दी से जल्दी उनकी सहायता की जा सके करनी चाहिए ताकि लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें और अगली फसल की बीजाई कर सकें।

चेयरमैन साहब, जनता सरकार के आने के बाद छोटे किसानों को भी राहत देने का प्रयत्न किया गया है। छोटे किसानों का सवा छः एकड़ तक का मालिया सरकार ने माफ किया है, यह बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। ट्रैक्टरों पर टोकन टैक्स माफ कर दिया, बिजली के फ्लैट रेट कर दिये और बैंकों के जो कर्जों की ब्याज दर थी वह 14 प्रति शत से घटाकर 11 प्रति शत कर दी है। यह बहुत ही अच्छे कदम सरकार ने उठाये है। लेकिन बिजली की फ्लैट रेट के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि 20 रुपये जो प्रति हौर्स पावर का फ्लैट रेट लेते हैं, यह बहुत ज्यादा लगता है। इसलिये इसको 12 रुपये प्रति हौर्स पावर कर दिया जाये तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं सरकार को कुछ सुझाव भी देना चाहता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं जल्दी जल्दी समाप्त करूँ, और सदस्यों ने भी बोलना है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो ट्रैक्टरों के मूल्य हैं, वे बहुत ज्यादा हैं। पहले के मुकाबले अब वे कम से कम दुगने हो गये हैं। पहले ट्रैक्टर 22 हजार में मिलता था वह अब 45,60 हजार में मिलता है। जो दरमियाने ट्रैक्टर या छोटे दरमियाने ट्रैक्टर हैं, उनको हमें किसान को मुहैया करवाने का प्रयत्न करना चाहिए। जो दो रियल ट्रैक्टर एक तो बाई लार्स और दूसरा डी.टी. 14 है, इनमें से डी.टी. 14 ट्रैक्टर तो जो बिल्कुल छोटे किसान हैं उनके लिये और जो बाई लार्स ट्रैक्टर है, यह मीडियम किसान के लिये मंगवाने के लिये हमारी सरकार को भारत सरकार से आग्रह करना चाहिए ताकि खेती का काम अच्छी तरह से हो सके। आज किसान यह समझता है कि हल से जोतना

इतना सफल नहीं है। वह यह समझता है कि बैलों के हल से खेती पूरी सफलता से नहीं की जा सकती। मैं इस बारे में एक और समस्या जो आम तौर पर किसानों को आती है, वह बताना चाहता हूँ। वह यह है कि कृषि मजदूर समय पर नहीं मिलते। बहुत मुश्किल रहती है। किसानों को जब जरूरत होती है, उन्हें मजदूर नहीं मिलते। इसलिये मेरा कहना यह है कि कम्बाईन थ्रै र्जर का भी जितना ज्यादा से ज्यादा और तरीके से मंगाये, लेकिन मेरा कहना यह है कि किसानों की दिक्कत को दूर करने के लिये कम्बाईन थ्रै र्जर ज्यादा से ज्यादा मंगाये जाये। फसल पैदा होने के बाद एक दाना भी खराब न हो, इसके लिये यह जरूरी है कि कम्बाईन थ्रै र्जर हो। जब फसल पुराने ढंग से ही काटकर उसको गाहते हैं तो इस के मुकाबले कम्बाईन थ्रै र्जर से प्रति एकड़ एक क्विंटल या दो क्विंटल के करीब फसल ज्यादा निकलती है। एक दाना भी बेकार नहीं जाता। भूसे के अरेंजमेंट के लिये हरे चारे का प्रबंध हो सकता है। साईंसदान भी यह कहते हैं कि जानवरों के लिये भेसा नहीं हरा चारा बारह मास मिलना चाहिए। इसके अलावा एक सुझाव मैं और देना चाहूंगा। अपने भूमि के ऊपर की सीलिंग तो कर दी लेकिन अनुत्पादक जोत के बोर में अभी तक हमने विचार नहीं किया। कम से कम गुजारे के लिये कितनी जमीन एक व्यक्ति के पास होनी चाहिए, इस बारे में मैं यह सुझाव दूंगा कि 4 हैक्टेयर तक की जोत उचित है। अगर किसी व्यक्ति के पास इससे कम जमीन हो तो उसका आगे के लिये बंटवारा समाप्त किया

जोयं यह बात इस नयी सरकार को तो कम से कम चोचनी चाहिए। हम आज तकसीम पर तकसीम करते जा रहे हैं। एक किल्ला अगर किसी के पास है ओरउसके दो लड़के है तो आधा आधा किल्ला बंटता है, अगर चार लड़के है तो एक चौभाई होगा। इस छोटे से जमीन के टुकड़े से किसी का भी गुजारा नहीं होता। मैं यह चाहूंग कि 4 हैक्टेयर के बारे किसी भी तरह से उसके टुकड़े नहीं किये जाये। अगर किसी के चार लड़के है और उसके पास 4 हैक्टेयर जमीन है तो एक लड़के को जमीन देकर बाकी के लड़को को सरकार जैसे फैंक्ट्रियां लगा रहा है, उनके लिये इस प्रकार का कोई न कोई रोजगार का प्रबंध किया जाये। आप देखिये, आजकल हो क्या रहा है कि 4 हैक्टेयर से कम जमीन वालो का गुजारा नहीं हो रहा है।

श्री सभापति: अब आप वाइंड अप कीजिये। आपने काफी समय ले लिया है।

चौधरी िाव राम वर्मा: मैं तो सभापति जी, पहले ही जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि लड़कियो का हिस्सा उनके बाप की जायदाद मे से नहीं, उसके पति की जायदाद मे से होना चाहिए। इसके गांव मे बहुत से झगड़े समाप्त होंगे। आज सारे के सारे किसान इस बात का इंतजार कर रहे है कि कब यह सरकार घोशणा करेगी कि इस किस्म का कानून बन गया है। मैं सरकार से यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि सरकार किसानो के भले के लिये बहुत ठीक से काम कर रही है, इसलिये

इस तरफ भी सरकार के भले के लिये बहुत ठीक से काम कर रही है, इसलिये इस तरफ भी सरकार को गोर करना चाहिए । एक बात ओर मैं सरकार का और ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि किसानों की उपज का उचित भाव आज तक भी उन्हें नहीं मिला। दूसरे लोगो के बारे मे तो मैं कुछ कहूं तो अच्छा नहीं लगता लेकिन एक किसान ही ऐसा वर्ग है जो न तो अपनी चीज का उचित भाव ले सकता है और न ही जो चीज वह खरीदता है उसका भाव वह कम करवा सकता है । दोनो तरफ से वह पिस रहा है। इसलिये सरकार को किसान को उसकी उपज का उचित भाव दिलाने के लिये प्रयत्न करना चाहिए। पिछले सै। न मे जब असेंबली का सै। न हुआ था, तो मेरो एक प्र. न का उत्तर मे सरकार की ओर से यहां पर यह बताया गया था कि गेहूं की लागत खर्च पिछले साल 1978 मे 127 रूपये 50 पैसे निकलता था। सरकार आज भी किसानों को उसकी उपज का मूल्य जो दे रही है वह 112 रूपये 50 पैसे है। अगर हम इस 112 रूपये 50 पैसे के मूल्य को ऐसा मूल्य मान ले जो कि सब किसानों को मिल जाता है तो भी उसको 15 रूपये क्विंटल का घाटा है। इसके अलावा उसको गुजारा चलाने के लिये कम से कम 10 प्रति। त और ज्यादा मिलना चाहिए था। मेर कहने का मतलब यह है कि उसको 140 रूपये प्रति क्विंटल मिलना चाहिए था। अगर हम उसे 140 रूपये का भाव कम से कम दिलवाये तो उसका कुछ भला हो सकता है। यह जितने टैक्स आप लगाते हो, यह इनडायरैक्टली किसान के ऊपर ही तो पड़ते है। क्योंकि वह अपनी

जिंस का ज्यादा भाव ले नही सकता ओर जो चीज वह खरीदता है उसका वह कम भाव करवा नही सकता। पिछले दिनों सन् 1973 मे चौधरी देवी लाल जी के नेतृत्व मे हमने एक आंदोलन किया था और इस वजह से हम कई बार जेलो मे भी गये हैं उस समय उस आंदोलन के कारण अगले साल कुछ भाव बढ़ाया गया था। गेहूं का कुछ भाव बढ़ने की वजह से उन्हें कुछ फायदा भी हुआ था। लेकिन उसके एकदम बाद खाद के भाव बढ़ गये। पहले जो यूरिया का एक बैग 53 रूपये का था वह एकदम बढ़कर 104 रूपये का हो गया इसी तरह से डी.ए.पी. का कट्टा जो पहले 66 रूपये का आता था वह भी 152 रूपये का हो गया। इधर उसकी फसल 105 रूपये क्विंटल बिकी थी तो उसको खाद के भाव भी बहुत ज्यादा देने पड़ गये थे। एक तरफ से जो उन्हें राहत दी गयी थी, वह दूसरी तरफ से निकाल ली गयी। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि किसान को आत भ लाभकारी मूल्य नही मिल पा रहा है। इसका कारण मैं यह समझता हूं कि हमारा नेतृत्व कमजोर हैं वे बेचारा घाटा खाते हुए भी पैदा करता रहता है। कभी हड़ताल नही करता, कभी बंद नही करता। अगर वह बोना बंद कर दे तो फिर खाने के लिये, उसके अपने गुजारे के लिये भी उसके पास गुंजाइश नहीं है। मैं चौधरी देवी लाल जी को वह दिन याद दिलाना चाहता हूं जब हम जेलो मे थे और वे सी क्लास मे भी रहे है। सरदार प्रकाश सिंह बादल जो आज पंजाब के मुख्य मंत्री है वे भी जेलों मे रहे है और चौधरी चरण सिंह भी केंद्र मे वित्त मंत्री है। यदि अब किसान को लाभदायक भाव न मिले तो कब

मिल पायेंगे ? मैं सरकार से किसानों के लिये कोई अन्यायोचित बात नहीं मांग रहा हूँ। मैं तो यह कह रहा हूँ कि किसानों को न्याय दिलाया जाये। जो उनका अधिकार है। वह उन्हें मिलना चाहिए। इसलिये आपको लड़ाई करनी चाहिए, नहीं तो किसान की हालत बुरी से बदत्तर होती जायेगी। मैं आपको एक सुझाव और रखना चाहता हूँ कि किसान जो खेत में बसना चाहते हैं, उनके लिये मकान बनाने के लिये बिना ब्याज के कर्जा दिया जाये। जो खेत में किसान रहते हैं, उसकी ज्यादा नहीं तो सवाई पैदावार हो सकती है। 20-25 प्रति एकर तक तो डैफिनेट बढ़ सकती है। इसलिये सरकार से मैं यह निवेदन करूंगा कि आवास की समस्या को गांवों में हल करने के लिये किसानों को जो खेत में रहना चाहते हैं, उनको वहां पर मकान बनाने के लिये बिना ब्याज के ऋण दिया जाये। इससे एक तो आवास की समस्या खत्म होगी और दूसरे पैदावार बढ़ेगी। अगर बहुत से किसान खेतों में जा बसेंगे तो आपको तथा देश को इस तरह से दो दो फायदे हैं।

श्री सभापति: अब आप वाइंड अप कीजिये।

चौधरी शिव राम वर्मा: मैंने तो अभी कुछ ही मिनट बोला हूँ। मुझे कृप्या और बोल लेने दीजिये।

श्री सभापति: आपको बोलते हुए 25 मिनट हो चुके हैं।
(व्यवधान व भाोर)

चौधरी विठ्ठल राम वर्मा: इसलिये जो लोग खेती पर बैठे हुए उनको सरकार विशेष ध्यान रखे। उनको बिना ब्याज के कर्जा दिया जाये। वह पेसा आपको अब य मिलेगा क्योंकि जिसके पास दो एकड़ जमीन भी है वह पैसा वापिस आने में कोई कठिनाई नहीं है। सरकार का पेसा मरेगा नहीं। चेयरमैन साहब, आपने देखा होगा कि कभी बाढ़ आ जाती है, कभी ओले पड़ जाते हैं और कभी किसी और तरह का नुकसान हो जाता है। इसलिये मेरा सरकार को सुझाव है कि सरकार कृषि के लिये नुकसान हो जाता है। इसलिये मेरा सरकार से सुझाव है कि सरकार कृषि के लिये बीमा योजना लागू करे। जिस तरह एक अभूतपूर्व ढंग से इस समय सरकार ने ओलो से फसल नष्ट होने पर 100, 200, 300 रुपये प्रति एकड़ सहायता किसान को देने की घोषणा की है जिसका एक हजार या आठ सौ रुपये का नुकसान हो गया उसको सरकार तीन सौ रुपया दे देगी तो इससे किसान की पूरी सहायता होकर उसे संभलने का अवसर तो मिलेगा परंतु इस प्रकार उसकी हालत पूरी तरह से सुधरेगी नहीं। अपनी हालत किसान खुद सुधारने की कोशिश तो करता है लेकिन जितनी सुधारनी चाहिए उतनी नहीं सुधारती है। अगर सरकार वाकई उनकी हालत सुधारना चाहती है। तो बीमा योजना लागू करे। चेयरमैन साहब, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ और वह यह है कि अब तक जो रिजर्वें हैं वे जातपात के आधार पर हैं उसकी वजाये जातपात के आधार बदलकर आर्थिक आधार पर किया जाये। इससे जातपात का नाम भी मिटेगा और चाहे किसी भी वर्ग के कमजोर

लोग होंगे उनकी सहायता हो सकेगी। इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह चार या पांच हजार रूपये प्रति वर्ष आय की कोई सीमा निर्धारित कर दे कि जिन लोगों की आमदनी इतने से कम होगी उनको नौकरियों में रिजर्वेशन दिया जायेगा तथा अन्य प्रकार की सुविधायें दी जायेगी। इससे हर गरीब आदमी का भला होगा। चेरमैन साहब, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। एक तो सरकार ने भूमि कर बढ़ाया है उसको समाप्त करना चाहिए। इस बारे में विचार भी नहीं आना चाहिए। मैं चौधरी देवी लाल जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि एक बार कांग्रेस की सरकार ने इसको बढ़ाने की बात की थी तो उस समय इसके खिलाफ आंदोलन करने की बात सोची गई थी। अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो यह उचित बात नहीं है और लोग कहेंगे कि पहले तो इस बढ़ौतरी के खिलाफ आंदोलन करते थे और अब खुद ही उस टैक्स को बढ़ा रहे हैं दूसरा टैक्स इस सरकार ने आबियाने पर बढ़ाया है। पता नहीं कि हमारे वित्त मंत्री श्री मूल चंद जैन किस लाइन पर सोचते हैं। 1967 में ये वित्त मंत्री बने थे और उस समय भी आबियाना बढ़ाने का प्रस्ताव लाए थे। उस वक्त भी उनको बताया गया था कि किसानों की हालत को समझिये और किसानों के ऊपर टैक्स नहीं लगाना चाहिए। आप जो टैक्स किसान पर लगायेंगे वह किसान को ही देना पड़ेगा। वह किसी दूसरे से वसूल नहीं कर सकता। अगर आप किसी दूसरे पर टैक्स लगायेंगे तो वह दूसरे पर पड़ता है लेकिन किसान पर लगाया हुआ टैक्स किसान को ही देना पड़ता है। हलवाइयों पर जो टैक्स आपने लगाया है वह तो

अपने ग्राहकों से वसूल कर लेगा। चेरमैन साहब, मैं आपको इसकी मिसाल देना चाहता हूँ। एक दफा एक आदमी एक हलवाई के पास लड्डू खरीदने गया उस हलवाई ने कहा कि भई अपना पल्ला फला। ग्राहक ने कहा कि मेरा कपड़ा चिकना हो जायेगा। हलवाई कहने लगा कि अगर तेरा कपड़ा ही चिकना होने लगा तो फिर मैंने क्या कमाया। मतलब यह है कि हलवाई ने निरी खांड लपेट रखी थी। चेरमैन साहब, मेरा कहने का मतलब यह है कि हलवाई तो उस टैक्स को ग्राहक से पूरा कर लेगा। वह घी कम लगायेगा या घटिया घी लगायेगा, चीनी ज्यादा लगा देगा लेकिन किसान के ऊपर लगा टैक्स तो किसान को ही देना पड़ेगा।

श्री सभापति: वर्मा जी आपको बहुत समय हो गया है। अब आप खत्म करें।

चौधरी शिव राम वर्मा: चेरमैन साहब, अब मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूँ। शिक्षा मिडिल स्कूल और हाई स्कूल तक तो शिक्षता से बढ़ानी चाहिए और खास तौर से लड़कियों की शिक्षा को खूब बढ़ाना चाहिए। तकनीकी शिक्षा को भी काफी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इस समय जहाँ पर भी तकनीकी शिक्षा दी जा रही है वहाँ पर दुगनी सीट्स पर देनी चाहिए। इस समय स्टेट में जो पोलिटेक्नीक चल रहे हैं उनकी तादाद दुगनी कर देनी चाहिए और उनमें जो विद्यार्थी प्रवेश के लिये जाते हैं उनकी तादाद भी निर्धारित सीट्स से दुगनी कर देनी चाहिए।

श्री सभापति: वर्मा जी, अब आप खत्म करें। जितना टाईम आपको दिया जाना चाहिए था वह आपको मिल चुका है। अब आप बैठ जायें। श्रीमती भान्ति देवी ।

चौधरी ि तव राम वर्मा: चेयरमैन साहब, अब मैं ला एंड आर्डर की बात कहना चाहता हूं (गोर).....

श्री सभापति: आप बैठ जाइयें आपका समय समाप्त हो गया है ।

चौधरी ि तव राम वर्मा: ला एंड आर्डर की पोजी तन यह है कि मंत्री का भय एस.पी. को नहीं है। एस.पी. का भय थानेदार को नहीं है और थानेदार का भय बदमा गो को नहीं है। इसलिये ला एंड आर्डर की स्थिति खराब है.....

श्री सभापति: वर्मा जी अब आप बैठ जाइये। मैंने दूसरे मेंबर को काल अपौन कर लिया है (व्यवधान) I am on my legs. Kindly sit down.

चौधरी ि तव राम वर्मा: बस मैं एक मिनट और बोलना चाहता हूं...

श्री सभापति: नहीं, अब आप बैठ जाइये ।

चौधरी ि तव राम वर्मा: अच्छा जी, मैं बैठ जाता हूं। आपा धन्यवाद ।

श्रीमती भांति देवी (कैलाना): चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से श्री मूल चंद जैन जो हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, ने जो बजट सदन के सम्मुख रखा है उसके बारे में अपने विचार रखना चाहती हूँ। चेयरमैन साहब, कई दिनों से इस बजट पर चर्चा चल रही है और हमारे जनता विधायक बड़े जोरों से इसका समर्थन कर रहे हैं और इसके बारे में कुछ सुझाव भी दे रहे हैं। चेयरमैन साहब, जैसे ही बजट की कापी हमारे हाथों में आई, प्रैस गैलरी की ओर से एक बात सुनाई दी कि यह बड़ा साहसिक बजट है। चेयरमैन साहब, यह गौर करने की बात है कि किसी कारण उन्होंने इस बजट को साहसिक बजट कहा है। उसके दिमाग में यह बात कैसे आई, यह सोचने वाली बात है। सब मानते हैं कि हरियाणा के अंदर किसान और मजदूर की सरकार है, उनका राज्य है। चेयरमैन साहब, मैं यह मानती हूँ कि बजट का अधिकांश भाग आज बिजली और सिंचाई के ऊपर और किसानों के ऊपर खर्च किया जा रहा है इसमें कोई दो राय नहीं है किंतु जैन साहब से बड़ी अपेक्षाएं थीं। चेयरमैन साहब, जब ये विधायक थे, मंत्री बनने से पूर्व बड़ी बड़ी बातें किया करते थे और अधिकारों के लिये बड़ा बोला करते थे। जब बजट पेश हुआ तो प्रैस वालों को आश्चर्य हुआ और मुझे भी यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने सब से पहले किसानों के ऊपर टैक्स लगाया है। क्यों लगाया है क्योंकि इनको पता है किसान मासूम हैं। चेयरमैन साहब, जैसा कि अभी वर्मा जी ने बताया है कि अगर किसानों के ऊपर टैक्स लगता है तो वह उसी को देना पड़ेगा और अगर किसी दूसरे पर टैक्स लगाता

है तो वह अपने ग्राहको को खांड का लौथड़ा बनाकर दे देता है लेकिन चेयरमैन साहब, किसान के साथ ऐसी बात नहीं है। पिछले साल जब चौधरी सतबीर सिंह ने बजट पे 1 किया था तो उन्होंने भी जल के ऊपर दस प्रति 1न अधिभार लगाया था लेकिन बाद में उस दस प्रति 1त अधिभार को वापिस लिया गया था और मैं समझती हूँ कि हाउस की भावनाओं को देखते हुए जैन साहब इसको वापिस लेने और हो सकता है कि इन्होंने ऐसा निपर्णय कर लिया होगा। अगर ऐसा निपर्णय नहीं किया है तो कर लेना चाहिए। यह बहुत अच्छी बात होगी। जैन साहब, दूसरी बात यह है कि बजट के पूर्व आपकी जो छवि थी वह बड़ी सुंदर छवि थी लेकिन बजट पे 1 होने के बाद वह छवि धूमिल हो गई हैं मुझे पता नहीं कि आपने मुख्य मंत्री महोदय की सलाह ली थी या नहीं या स्वयं ही यह बोझा अपने ऊपर ले लिया। मैं सोचती थी कि सलाह ली थी या नहीं स्वयं ही यह बोझा अपने ऊपर ले लिया। मैं सोचती थी कि जैन साहब बड़ी सूझ बूझ के आदमी है, इंटेलीजेण्ट है, वे बहुत ही दूर अंदा 1ी कर भार लगाएंगे लेकिन जैन साहब ने जो उन बड़े उद्योगपतियों को छोड़ा है जोकि दिल्ली और फरीदाबाद में बड़े बड़े उद्योगों के मालिक हैं और मजे लूट रहे हैं, कारों में चलते हैं, करोड़ों की सम्पत्ति के मालिक हैं, जिनके कुत्ते भी दूध पीते हैं बल्कि उनके स्थान पर उन गरीब आदमियों को छोड़ा गया है जिनके पास रहने के लिये मकान नहीं है, खाने के लिये कुछ नहीं, पहनने के लिये कपड़ा नहीं है.....(1ोर).

.....

डा. वृज मोहन गुप्ता: चेयरमैन साहब, हमारी आदणीय बहन जी ने यहां हाउस मे इंडस्ट्रीयलिस्ट की बात कहीं है कि वे मजे लूट रहे है। मजे की परिभाशा मेरी बहन समझाने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती भांति देवी: चेयरमैन साहब, अगर डाक्टर बृज मोहन 'मजे' की परिभाशा जानते तो बड़े अफसोस की बात है। फिर इन को हरियाणा के अंदर नही रहना चाहिये। इनको तो दिल्ली और फरीदाबाद के अंदर जाकर रहना चाहिए। मैं कह रही थी कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीयलिस्ट है, वे कारो मे घूमते हे, मजे लूटते है और उनके तो कुत्ते भी दूध पीते है लेकिन हमारे हरियाणा के अंदर बच्चो को लस्सी भी नही मिलती है, फिर डाक्टर बृज मोहन जी पूछते है कि मजे की परिभाशा क्या है ? चेयरमैन साहब, आज किसान की हालत बड़ी नाजुक है, वह कहीं तो पटवारी से पीड़ीत है.....(गोर व व्यवधान)

श्री सभापति: देखिये, मैं बिजिटर्ज गैलीरी मे बैठे हुए लोग से प्रार्थना करुंगा कि वे यहां पर किसी किस्म का भाोर या तालियां न बजाये।

श्रीमती भांति देवी: तो मैं कह रही थी कि कृशक आज बुरी तरह से पीड़ित है कहीं जिलेदार से पीड़ीत है, तावान से पीड़ीत है और दूसरी तरफ उनके इलाके को बेलदार काट देते है जिनका सीधा किसान पर पड़ता है और उनक चैन साहब ने सवा

छ: एकड़ से ऊपर भूमि रखने वाले किसान पर सवा 33 परसेंट सरचार्ज लगा दिया है पर मुझे खुशी होती है अगर सरकार कोई सीमा निर्धारित कर देती कि जिन के पास 15 या 18 एकड़ से ऊपर भूमि हो, उस पर यह टैक्स लगाया जायेगा। चेयरमैन साहब, पिछले दफा सरकारने सवा एकड़ तक का जो मालिया माफ किया था, वह भी किन्ही विशेष परिस्थितियों के कारण ही किया था, इस समय मे उसके डिटेल् मे हनी जाना चाहती कि वे कारण क्या थे ? किसानो को जो हमारी सरकार ने अपने घोशणा पत्र मे विवास दिलाया था, उसको तो पूरा किया गया है।

श्री भामदेर सिंह: चेयरमैन साहब, बहन जी ने जिन परिस्थितियों का जिकर किया हे, उन परिस्थितियों के बारे जरा एक्सप्लेन कर दे ताकि सदन को भी इस बारे जानकारी प्राप्त हो सके।

श्रीमती भांति देवी: यह हमारी अपनी पार्टी का सवाल है, चौधरी भामदेर सिंह जी को क्यों इस बात की चिंता हो रही है ? चेयरमैन साहब, सवा छः एकड़ तक जो मालिया सरकार ने साफ किया था वह है कोई लगभग 1 करोड़ 40 लाख और अब इन्होंने किसानो के ऊपर 1 करोड़ 30 लाख के करीब टैक्स लगाये है, पहले से यानि 10 लाख कम से टैक्सज लगाये गये है। आप देख लीजिये कि हमारी जनता सरकारान ने किसानानो को कितनी छूट दी है, मैं हैरान हूं कि जैन साहब ने पता नही किस भूल के कारण ऐसा कर दिया है, वरना तो मामला साफ था। चेयरमैन साहब,

इससे आगे मैं राज्य परिवहन के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे भाई बूरा साहब ने भी एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा था कि हमारे हरियाणा प्रांत में परिवहन की हालत अच्छी नहीं है। चेयरमैन साहब, हमारे सभी भाई जानते हैं कि परिवहन की हमारे हरियाणा में कैसे बुरी हालत है। रोहतक के अंदर सात बसों खराब पड़ी हैं और वह वर्क आप में खड़ी कर रखी है। इसी प्रकार से मैं सोनीपत के अंदर भी खराब बसों के आंकड़े बता सकती हूँ परंतु मुझे खेद है कि यहां पर चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहब ने कितने गलत आंकड़े दिये हैं।

चेयरमैन साहब, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस सरकार ने 60 परसेंट के करीब भाड़े वृद्धि की थी और इसके इलावा हमारी जनता सरकार साढ़े 12 परसेंट भाड़ा और बढ़ाना चाहती है, इसलिये मैं जैन साहब से यह पूछना चाहती हूँ कि ऐसा करने से क्या एक छोटे से छोटे आदमी पर, गरीब परिवारों पर जो कि बसों में सफर करते हैं, इसका असर नहीं पड़ेगा? मुझे खुशी होती अगर सरकार की आमदनी बढ़ाने के लिये कोई और तरह का तरीका निकालते। इसलिये मेरी जैन साहब और अपनी सरकार से अपील है कि कम से कम गरीबों को इससे राहत जरूर मिलनी चाहिये और मुझे आशा भी है कि वे भविष्य में कभी ऐसा नहीं होने देंगे।

चेयरमैन साहब, इससे आगे मैं कर्मचारियों के बारे में भी दो चार बातें यहां हाउस के सामने रखना चाहती हूँ। इस

बारे में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मामला यहां हाउस में आया और हमारे मुख्य मंत्री महोदयने यह न देखते हुए कि कितने व्यक्ति इससे प्रभावित हैं, कह दिया कि मुझे कुछ रुचि नहीं है। यहां पर कर्मचारियों की सामान्य रिपोर्ट का जिक्र चला रहा था जिसको एवरेज रिपोर्ट कहते हैं। जो कर्मचारी, अधिकारी हैं और बेचारे भारीफ व ईमानदार हैं और अपने कर्तव्य का पालन पूरी तरह से निभाना चाहते हैं, उनको तंग करने का करने का सामान्य रिपोर्ट का रास्ता बीच में से निकाल लिया गया है और जब कभी उन बेचारों की बदकिस्मती से 15 या 20 सालों के बाद प्रमोशन वगैरह का चांस आता है तो सामान्य रिपोर्ट का हवाला देते हुए, उनको बीच में ही लटकाया जाता है, देखिये। कितना बड़ा खिलवाड़ कर्मचारियों के साथ हो रहा है? जो कर्मचारी ईमानदारी से काम करते हैं, अपने कर्तव्य का पूरी तरह से पालन करते हैं आप इंसपैक्ट करवा के देख लीजिये जो चम्चागिरी में विवास नहीं रखते, वे यूंही के यूंही बैठे रहते हैं। ऐसा होता है कि ऐसा कर्मचारियों को लटकाया जाता है। इसलिये मैं अपने चीफ मिनिस्टर साहब से यह प्रार्थना करूंगी कि यह सामान्य रिपोर्ट वाला सिलसिला खत्म किया जाये और जिनके विरुद्ध कोई बैड या सामान्य रिपोर्ट्स हो, उनको साफ तौर पर रिमार्कस कनबे किये जायें।

चेयरमैन साहब, अब मैं अध्यापकों के बारे में यहां पर कहना चाहती हूँ आप को पता ही है कि हरियाणा में जनता राज्य को लाने का प्रमुख पार्ट अध्यापकों ने ही अदा किया है..... ।

डा. बृज मोहन गुप्ता: चेयरमैन साहब, आपने 20-20 मिनट सभी के लिये बोलने का समय रखा है। आधा आधा घण्टा अगर मੈंबरोँ को बोलने की इजाजत दी जायेगी तो यह उचित नहीं रहेगा।

श्रीमती भांति देवी: मैं अध्यापकों के बारे में जिकर कर रही थीं अगर पिछली बंसी लाल की सरकार के साथ किसी ने टक्कर ली थी तो वह हरियाणा के अध्यापकों ने ही ली थी चाहे आप इसको अपोजी इन कह लो या हरियाणा के अध्यापक का नाम दे दो। इस बात को स्वयं बंसी लाल जी भी स्पीकार किया था कि अगर कोई अपोजी इन है तो वह अध्यापक गर्व ही है। चेयरमैन साहब, एक और बड़ा अहम मसला है जोकि मैंने पहले भी रखा था। वह था मकान के भते और मैडिकल के बारे में। कई बार प्रयास करने के बावजूद भी गाँवों के लोग इस प्रकार की सहूलियतों से वंचित रह जाते हैं और जो चण्डीगढ़ के अंदर कर्मचारी बैठे हुए हैं, आप आंकड़ें मंगवा करके देख लीजिये। इस बात की इंकवारी के लिये मेरे भाई सतबीर सिंह जी ने पग उठाये थे लेकिन यह मामला आज तक लटक रहा है, वे तो महीने में कई सौ रूपये मैडिकल भत्ते के ले जाते हैं और जो देहात में बैठे हैं उनको कुछ भी नहीं मिलती है, इसलिये मैं चाहूँगी कि यह

सहूलियत चाहे आप चार चार या पांच पांच रूपये की भावल मे दे लेकिन सब को मिलनी चाहिये। इस पर हर कर्मचारी का अधिकार होना चाहिये। होता यह है कि कुछ कर्मचारी तो दो दो सौ और अढ़ाई अढ़ाई सौ रूपये मैडिकल भत्ता ले जाते है लेकिन बाकियो को कुछ नही मिलता। इसी तरह से जो कर्मचारी भाहरो मे रहते हे उनको हाउस रेंट की भी सुविधा दी जाती है। मैं यह नही चाहती कि उनको यह सुविधा न दी जाये लेकिन मैं तो यह चाहती हूं कि जो कर्मचारी देहात मे काम करते हे उनको भी यह सुविधा दी जानी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि जो यहां पर अध्यापक विधायक है वे मेरी इस बात का समर्थन करेंगे और इनके इलावा जो दूसरो विधायक है वे भी इसकी पुरजौर ताईद करेंगे। इसके बाद मैं एच.सी.एस. और आई.ए.एस. आफसरो के बारे मे कहना चाहती हूं कि इनको हर विभाग मे थोप दिया जाता है। मेरी प्रार्थना यह है कि 50 प्रति ात कोटा टैक्नीकल आदमियो के लिये रखा जाना चाहिये जिनको नीचे से लेकर ऊपर तक का तजुरबा होता है। आप रोड़वेज मे रेखे। डिपो का जो जनरल मैनेजर होता है वह भी एच.सी.एस. को लगा दिया जाता है। एक इन्होंने एक डी.एस.पी. लगाया हैं यह भी तजुरबा देख लेंगे कहां तक कामयाब होता है। पुलिस एक डी.एस.पी. लगाया है। यह भी तजुरबा देख लेंगे कहां तक कामयाब होता है। पुलिस के बारे मे हमे लोग जानते है कि ये लोग क्या करते है। कहीं बीमारी को दूर करते करते बीमारी और न बढ़ा ले। इसलिये मेरील प्रार्थना है कि जिन लोगो की इतनी इतनी सर्विस हो गई है उनका भी ध्यान रखा

जाये। यानी उनको मिलना चाहिए। चेयरमैन साहब, मैं सरकार से यह भी प्रार्थना करूंगी की प्राइमरी निदेशालय को अलग कर दिया जाये ताकि जे.बी.टी. टीचरो के कैंसिज का जल्दी से निपटारा हो सके। इसके बाद मैं मुख्य मंत्री जी को कहूंगी कि हमारे सोनीपत जिले में अब तक बस डिपो नहीं बना है। वहां पर 29 तारीख को बिल्डिंग तैयार हो जायेगी इसलिये मेरी प्रार्थना है कि अगला जो डिपो बनाया जाये वा सोनीपत में ही बनाया जाये। एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहती हूँ कि हमारी जनता सरकार ने जितनी आजादी बहाल की है उतनी भायर कांग्रेस वालो ने कभी सोची भी न हो। आज सब लोग सुख से सो रहे है। इसके अलावा मुख्य मंत्री जी से मैं थोड़ी से और उपेक्षा करूंगी और मुझे उम्मीद है कि मंत्रिगण तथा अन्य विधायक भी मेरे से सहमत होंगे। यह बात यह है कि हम लोग गरीब परिवारो से आये है और जो अब से पहले राज कर चुके है, वे बड़े परिवारो से ताल्लुक रखते थे। उनको यह नहीं पता था कि गरीबी क्या होती है। उनको तो एक ही लगन थी कि किसी तरह से धन बटोर लिया जाये। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें कोठियो, कारो और टैलीफोन का खर्च घटाना चाहिए ताकि जनता को इस चीज से एक नई झलक नजर आ सके। इसके अलावा जो विधायक बड़ी बड़ी कार्पोरेट्स के चेयरमैन है उनको भी अस्तीफा देकर मैदान में आ जाना चाहिये। ऐसा करने से लोग बहुत खुश होंगे। भायद जैन साहब मेरे से नाराज हो कि मैं सारे टैक्सो को ही वापिस करवाना चाहती हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि आप एक दो

टैक्सों को छोड़ कर बाकी सारे टैक्स वापिस ले लो। अगर आप बगैर टैक्स के भी देहात का विकास करना चाहते हैं तो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। आप मगर इंकम टैक्स और सेल्ज टैक्स की सैंट-परसैंट वसूली कर ले तो मेरा ख्याल है आपको कोई भी नया टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सुझावों के साथ मैं आपका भुक्रिया अदा करते हुए अपना स्थान लेती हूँ।

कामरेड भांकर लाल (सिरसा): चेयरमैन साहब, यह बजट जनता का बजट है इसको तीन भागों में बांटा जा सकता है। एक तो यह कि जब से हमारी जनता सरकार बनी है इससे जनता की भलाई के कौन कौन से काम किये हैं। इस बारे में मेरे काफी साथियों ने भी बताया है। जैसे फलडछ आए उस समय हमारी सरकार ने जनता के हिले बहुत ज्यादा काम किया हैं यह काम सराहना के लायक है। दूसरे इस सरकार ने किसानो के कलये ब्याज की दर 14 प्रति ात से घटाकर 11 प्रति ात कर दी यह भी बहुत सराहनीय कदम हैं जब से जनता सरकार बनी है तब से हमारी सरकार की हर यही कोि ा ा रही है कि वह किसान को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाए। इसमें कोई दो राय नहीं है मगर किसी कारण से इस बजट में कुछ बाते रही गई है। वे भी यहां बतानी बहुत जरूरी है। मेरे दोस्तो। इस बजट के अंदर एक सवाल जो हाउस के अंदर ज्यादा उठाया जाता है वह है भाहरी सम्पदा के बारे में। यह सवाल चाहे कोई भी सरकार हो, उसमें उठाया जाना अच्छा नहीं है। सवाल तो इस वक्त कमाने वाले और

लूटने वाले का है। कई कहते हैं कि यह बजट लूटने वालों पर लागू होता है और कमाने वालों के ऊपर तक जो भी टैक्स लगते हैं, चाहे बसों के किराये पर टैक्स लगाया गया हो, यह तो गरीब जनता पर ही लगता है क्योंकि कारों पर चलने वाले तो बसों में जाते नहीं हैं। इसलिये मैं कहता हूँ कि बसों के किराये में जो इस सरकार ने वृद्धि की है। जो 12½ प्रति शत भाड़ा बढ़ाया है, इसे सरकार वापिस ले। यह ठीक है कि सालों से लगातार किराये बढ़ते जा रहे हैं। किसी बात की हद होती है इसके अलावा यह भी जरूरी है कि जिन बसों में लोग चलते हैं उनकी हालत बहुत खराब है, उनकी हालत को सुधारा जाये। इन बसों की काफी घटिया हालत है। दिल्ली से जो बस चण्डीगढ़ के लिये आती है। उसकी खिड़कियाँ और दरवाजे टूटे हुए हैं। यह सबसे अच्छी रोड है इस पर तो चलने वाली बसों की अच्छी हालत होनी चाहिए। हरियाणा रोडवेज की है। जो बसें हरियाणा के कच्चे रास्तों पर चलती हैं वे तो और भी टूटी फूटी हालत में हैं। लम्बे रूट की बसें अगर रास्ते में खराब हो जाये तो उनको उनके डिपो पर ही ठीक कराने के लिये लाया जाता है। अगर चण्डीगढ़ डिपो की बस है और वह करनाल के नजदीक खराब हो जाती है तो उसे बजाये नजदीक के डिपो करनाल में ले जाने के लिये खींच कर चण्डीगढ़ लाया जाता है। अगर दिल्ली के अंदर कोई बस खराब हो, चाहे वह किसी भी डिपो की बस है उसे उसके डिपो पर ही ले जाया जाता है। उसको नजदीक के डिपो पर ले जाया जाना चाहिये। चण्डीगढ़ डिपो वाली बस को ठीक करवाने के लिये

करनाल भी तो ले जाया जा सकता है । इसी तरह सरकार को काफी पेट्रोल का खर्च उठाना पड़ता है, राजस्थान में भी लगता है, दिल्ली में भी लगता है परंतु सबसे ज्यादा सेल्ज टैक्स हरियाणा में हमारी सरकार ने लगा रखा है । यह टैक्स चाहे किसी चीज पर लगे लेकिन हमारे यहां ज्यादा है । दिल्ली में माचिस पर 5 प्रति 100 सेल्ज टैक्स लगता है परंतु हमारे हरियाणा में यही सेल्ज टैक्स 7 प्रति 100 लगता है । यह तो हमारी सरकार दिल्ली सरकार को मजबूर करे कि सेल्ज टैक्स बिल्कुल न लगाया जाये अगर वह सरकार दबाव में नहीं आती तो आप भी उसी दर से सेल्ज टैक्स लगाये जो दूसरी स्टेट्स में है ।

इसी तरह से यहां पर गांवों में उद्योगीकरण की बात चल रही है । यहां पर किसानों और देहातों की बात होती है लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं है । सेल्ज टैक्स को खत्म किया जाये हमारे घोशणा पत्र के अंदर कहा गया है कि हरियाणा सरकार सेल्ज टैक्स खत्म कर देगी । इसमें कोई दो बात नहीं है । मेरे दोस्तों ने भी कुछ बातें की हैं । मैं इस बारे में कहूंगा कि चौथी श्रेणी के कर्मचारी आज धरना दे कर किया है और तीसरी श्रेणी के कर्मचारी क्लर्कस जो लगे हुए हैं, उन्होंने क्या करसूर किया है ? पिछले दिनों जब हजारों मास्टर्स को रेगुलर किया गया है तो इन 7 हजार क्लर्कों को क्यों नहीं रेगुलर किया गया ? एक बड़ी खुशी की बात और है कि हमारे चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी और चीफ मिनिस्टर साहब ने उससे परसों बातचीत की है और कुछ

वायदा भी किया है। इन गरीब लोगो का भला करना चाहिए । हमे कहते है कि समाज का भला हो, समाज मे सबसे पहले वे लोग आते है जिनकी जमीने है उनकी जमीनों पर साढ़े 33 प्रति ात लगान लगाया जा रहा है। इसके साथ आबियाने पर 10 प्रति ात टैक्स लगया गया है। सरकार पानी का एक रूपये तक फीस किलले लगान लेती है ओर आबियाना 25 रूपये से 45 रूपये तक लेती है, यह मै अंदाजन कह रहा हूं। तरह तरह की फसल पर तरह तरह की दर से आबियाना लगता है। सबसे पहले 6.25 एकड़ जिस किसान के पास जमीन हे उस पर लगान नही लगता परंतु उस पर पानी का टैक्स लगता है। जब सरकार ने यह कह दिया है कि 6.25 एकड़ जमीन वाले किसान को सरकार मदद देगी तो उनकी जमीन पर से मालिया यानी रेवेन्यू खत्म किया जाये। सबसे बड़ी बात यह है कि यह खेती टोटे का सौदा है मगर यह अच्छा फायदे वाला काम होता तो ये पढ़े लिखे लोग, वकील और आई.ए. एस. अफसर सभी लोग खेती न करने लग जाते। खेती टोटे का सौदा है घाटे का सौदा है। दूसरे मूलको मे जैसे अमेरिका आदि मे 50 प्रति ात लोग खेती करते है उसके मूकाबिले पंजाब और हरियाणा में 80 प्रति ात लोग खेती पर निर्भर करते हैं – चाहे वे खेतिहर मजदूर हों, चाहे छोटा किसान हो, चाहे मुजारा हो, चाहे रेढ़ेवाला हो। यह खेती का सौदा टोटे वाला है। खेती पर हर किस्म के जो लगान लगते हैं, वे माफ कर देने चाहिए। मैं इसमें कोई दो राय नहीं रखता। दूसरी बात मैं यह कहता हूं कि सरकार काफी फिजूल खर्च करती है उनका इस्तेमाल बन्द किया जायें

.... (विघ्न) तीसरे जो कारपोरेट्स के चेयरमैन कम से कम 30 बना रखे हैं और 22-23 और बनाना चाहते हैं, उनकी संख्या कम होनी चाहिए। इन पर करोड़ों रूपया खर्च किया जाता है। ये सरकार के सिर पर सफेद हाथी की तरह से है। चेयरमैन साहब, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि यह जो लम्बी कारें और यह जो बड़े बड़े बंगले व पर्यटन केन्द्र भाहरों में बने हुए हैं जब तक यह परिस्थितियाँ ठीक नहीं होंगे तब तक गरीबी दूर नहीं हो सकती। आप इन सब चीजों को बनाना बंद कर दें और गरीबों का काम करें। चेयरमैन साहब, मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर गरीब पाताल में बैठा हुआ है और अमीर आसमान पर बैठा हुआ है जब तक अमीर को आसमान से नीचे और गरीब को पाताल से ऊपर नहीं लाया जायेगा तथा इनको बीच में नहीं लाया जायेगा तब तक गरीबी दूर नहीं होगी। इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूँ कि काला धन, नम्बर दो का धन जिस किसी के पास सरकार को पता लगे वह धन उससे छीन करके सरकार अपने कब्जे में ले ले और उसे सरकार के खजाने में डाला जाये ताकि इस घाटे को पूरा किया जा सके दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि जो भाराब के ठेके हैं, जो निली चीजें हैं और यह जो ऐगोआराम की बड़ी बड़ी चीजें हैं इनके ऊपर सबसे ज्यादा टैक्स लगाये जायें और गरीबों पर टैक्स न लगाए जाये।

अब मैं हलवाईयों के बारे में कहना चाहता हूँ कि उन पर टैक्स न लगाये जायें। हलवाई पैसे का हिसाब नहीं रख सकता

है क्योंकि कोई एक रूपये की मिठाई लेता है और कोई चार आने की मिठाई लेता है। हलवाई मैदा खरीदता है तो उस पर भी सेल्ज टैक्स लगता है। और यदि दूसरी जीच कोई खरीदता है तो उसे पहले ही टैक्स लग जाता है। इसलिये मैं प्रार्थना करता हूँ कि हलवाईयों पर टैक्स न लगाया जाये। चेयरमैन साहब, मैं एक बात साफ कह देता हूँ कि जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस सरकार से अच्छी सरकार है। इस सरकार में 20 परसेंट का नुक्स आया है उसको भी हम ठीक करेंगे और हम इसको रास्ते पर लाएंगे। कांग्रेस के भासन में तो सौफीसदी खराबी आ गई थी। जब श्रीमती इन्दिरा गांधी कहीं पर भी आती थी तो श्रीमती इंदिरा गांधी को लाखों रूपये की मालाएं डाली जाती थी.....(गोर व व्यवधान)..... श्रीमती इंदिरा गांधी को खुद करने के लिये उसके गले में लाखों रूपये की.....(गोर)

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: आन ए प्वायंट आफ आर्डर। कामरेड भांकर लाल जी ने यह जो मालाओं का जिक्र किया है तो क्या इन्होंने जो किसान रैली के लिये ब्यान दिया था, उसे विदड्रा करेंगे ?

श्री सभापति: चौधरी जगजीत सिंह पोहलू जी, आप बैठिये।

कामरेड भांकर लाल: चेयरमैन साहब, आज जनता में पूंजीवादी धारणा फैलती जा रही है। किसी नेता को चांदी से

तोला जाता है, किसी नेता को नोटों की थैलियों से खुदा किया जाता है और किसी नेता को इस देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा पूंजी दिखा करके लुभाया जाता है। यह बीमारी सबसे ज्यादा कांग्रेस भासन में थी। इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि 23 तारीख को हमारे हरियाणा के कुछ लोगों ने 2 करोड़ रुपये इकट्ठे करके दिल्ली में चौधरी चरण सिंह जी को दिये। (गोर)

श्री सभापति: कामरेड भांकर लाल जी, अब आप बैठिये, आपका समय हो गया है। अब डाक्टर मंगल सैन बोलेंगे।

कामरेड भांकर लाल: चेयरमैन साहब, अभी मैंने अपना प्वायंट खत्म नहीं किया। मुझे अपना प्वायंट खत्म तो कर लेने दीजिये.....(व्यवधान)

श्री सभापति: भांकर लाल जी, आप बैठियें आपका समय समाप्त हो गया है और मैंने डाक्टर मंगल सैन जी को कालअपोन कर लिया है। आ बैठिये।

उद्योग मंत्री (डा. मंगल सैन): चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि पिछले तीन दिनों से सदन में बजट पर अपोजीशन की ओर से भी और ट्रेजरी बेंचिज की ओर से भी विचार प्रकट किये जा रहे हैं। मैं बहुत खुदा हूँ कि लोगों ने बड़े कंस्ट्रक्टिव सुझाव दिये.....

राव बीरेन्द्र सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। मैं यह कहना चाहता हूँ कि कामरेड भांकर लाल जी अपना एक प्वायंट कहना चाहते थे वह उनका पूरा नहीं हुआ था। किसी मेंबर का प्वायंट जब तक पूरा नह हो तब तक किसी दूसरे मेंबर को टाईम नहीं मिलना चाहिए।

श्री सभापति: उनका समय हो गया है, आप बैठियें

डा. मंगल सैन: राव साहब ने कहा कि उनका प्वायंट पूरा नहीं हुआ है। यह उनकी गलतफहमी है। यह फैसला चेयर ने सोच समझ कर किया है। खैर, मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि सदन में बजट पर बहस चल रही है। मैंने अपोजी इन की तरफ से काफी बातें सुनी है। चेयरमैन साहब, बाकी उनकी बातों का जवाब तो मेरे आदरणीय वित्त मंत्री जी दे देंगे। मैं तो अपने विभाग के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। आज मेरे भाई भामोर सिंह सदन से वाक आउट कर गये और फिर वापिस भी लौट आये। 25 मिनट तक सदन में बोल भी लिये और बाद में वाक आउट भी कर गये ताकि कल अखबार में उनका नाम आ जाये.....

राव बीरेन्द्र सिंह: जो आप बोल रहे हैं, क्या यह आपके विभाग से ताल्लुक रखता है ?

डा. मंगल सैन: जी हां, जो कुछ अपोजी इन ने कहा है उनके सवाल का करारा जवाब देना मेरा फर्ज बनता है। कुछ माननीय सदस्य तो स्वागत में लगे हुए थे और भीड़ भाड़ में व्यस्त

थे। ठीक है उन्होंने व्यस्त होना ही था, उनका काम था, वहां जाना ही था। चेयरमैन साहब, जनता पार्टी की सरकार के सत्ता में आने के बार औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी सराहनीय प्रगति हुई है। यह ठीक है कि हरियाणा स्टेट मूल रूप से बेसिकली एक कृषि प्रधान स्टेट है, जैसा कि बजट के आंकड़ों से जाहिर होता है....

श्रीमती सुशमा स्वराज: आन ए प्वायंट आफ आर्डर । सभापति महोदय डा. मंगल सैन जी अपने विभाग के बारे में जवाब देने के लिये खड़े हुए हैं। मैं आप से कहना चाहती हूँ कि अभी तो बजट पर चर्चा चल रही है और अभी तो बहुत से सदस्यों ने बजट पर बोलना है। इनके विभाग के बारे में कई भाक भुबहा, संदेह, भ्रान्तियां सामने आयेंगे जिनका जवाब इनको देना पड़ेगा। अगर डा. साहब बहस समाप्त होने के बाद बोलें और उसके बाद जवाब दें तो सदस्यों को तसल्ली हो जायेगी। अगर बीच में बोलेंगे तो जो संदेह हमने कल की बैठक में सदन के सामने रखने हैं, वे बिना जवाब दिये रह जायेंगे और अगर दोबारा बोलेंगे तो सदन का समय नष्ट होगा। वैसे भी सारे सदस्यों के बोलने के बाद ही मिनिस्टर जवाब देता है ताकि सारे सदस्यों की तसल्ली हो जाये।

चौधरी राम लाल वधवा: चेयरमैन साहब, हाउस की कन्वेँशन है कि अगर मिनिस्टर बैठा हो तो वह बतौर मेंबर बोल सकता है। जहां तक जवाब देने का ताल्लुक है, जवाब देने की ज्वायंट रिस्पंसिबिलिटी होती है और अगर कोई बात रह जाये तो फाइनस मिनिस्टर जवाब देंगे। ऐसी कोई कन्वेँशन नहीं है कि

बजट डिस्कान के बीच में मिनिस्टर को जवाब देने की इजाजत न हो, वह बीच में बोल सकता है।

श्रीमती सुशमा स्वराज: अगर वे सदन के सदस्य की हैसियत से बोले तब तो ठीक है लेकिन डा. साहब बोलने के लिये खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि उनके विभाग के बारे में कुछ बातें कही गई हैं और इन्होंने उद्योग विभाग के बारे में बोलना शुरू कर दिया। वे सदस्य ही हैसियत से नहीं बोल रहे, मिनिस्टर की हैसियत से बोल रहे हैं।

Dr. Mangal Sein: I can do it both ways. Madam, you are not the final authority to judge.

श्री सभापति: कोई भी मिनिस्टर हाउस में अपनी क्लैरिफिकेशन दे सकता है (व्यवधान)

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: चेयरमैन साहब, जब तक सारे मैनबर साहिबान न बोल ले तब तक मिनिस्टर को बोलने की इजाजत न दी जाये (व्यवधान)

श्री सभापति: अगर मिनिस्टर किसी बात के बारे में जवाब देना जरूरी समझते हैं तो वे जवाब दे सकते हैं, दो दफा बोल सकते हैं (व्यवधान) आज बहस खत्म नहीं हो रही। (व्यवधान) मैं सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि अभी बजट पर बहस आगे चलेगी।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह: मैम्बर साहिबान को बोलने का टाईम अलाट होता है उसी तरह मिनिस्टर को आर्टिम अलाट होता है (व्यवधान) रिप्लाई देने का टाईम मिनिस्टर की अलाट होता है...

.....

Mr. Chairman: I have given my ruling. A Minister can clarify any point at any time during the debate.

Chaudhri Birender Singh: He is not participating in the debate as a member because he has said that he is giving a reply to the points relating to his department.

डा. मंगल सैन: चेयरमैन साहब, मुझे खेद है और मेरी हम्बल सबमिशन है आदरणीय मੈंबरों से कि जो भाको भुबहा, इतराजात, खद गाजात रह जायेंगे, वे ऐप्रोप्रिएशन बिल पर बहस करते वक्त बता दें, उनका जवाब मैं पूरा दूंगा, लेकिन इस वक्त मुझे बोलने का अधिकार है और यही कन्वैन्शन है। बहन जी, नयी नयी मैम्बर बनी है, जरा रूल्ज का उठकर देखे ले तो सब मालूम हो जायेगा। चेयरमैन साहब, मैं कह रहा था कि जब से जनता पार्टी सत्ता में आई है.....

कामरेड भांकर लाल: चेयरमैन साहब, अभी मैंने बहुत कुछ कहना है, मुझे और टाईम दीजिये (व्यवधान)

श्री सभापति: मैंने आपको बैठने के लिये कह दिया है। लेकिन अब भी आप खड़े हैं। अगर ऐसे ही खड़ा रहना चाहते हैं तो अपनी मर्जी। (व्यवधान)

स्वामी अग्निवे T: आन ए प्वायंट आफ आर्डर। चेयरमैन साहब, कामरेड साहब कुछ बातें कहने वाले हैं, उनकी बात अभी पूरी नहीं हुई है। (व्यवधान) अगर आप पहले यह कह देते कि दो मिनट में खत्म कर दो.....(व्यवधान व भाोर)

Mr. Chairman: This is no point of order. Please take your seat.

डा. मंगल सैन: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब से जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से सरकारने ग्राम विकास के लिये, गांवों में रहने वाले किसान, मजदूर के लिये और अनुसूचित तथा पिछड़ी जातियों की उन्नति और विकास के लिये हमें 11 प्रयत्न मिल रही हैं और यही कारण है कि सरकार द्वारा बजट का बहुत बड़ा हिस्सा ग्रामीण विकास की ओर लगाया जा रहा है। चेयरमैन साहब, सरकार ने उद्योग की ओर ध्यान दिया है.....

राव बीरेन्द्र सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। चेयरमैन साहब, हमारे माननीय सदस्य कामरेड भांकर लाल जी खड़े हैं, वे कुछ कहना चाहते हैं। उनको बैठा कर ही हाउस की कार्यवाही आगे चलनी चाहिए (व्यवधान) हाउस की कार्यवाही चलाने के लिये आर्डर रैस्टोर किया जाये या मॅबर साहब को बैठाया जाये। वे इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनको बोलने का मौका दिया जायेगा (व्यवधान)

श्री सभापति: उनको बैठने के लिये कह दिया गया था
(व्यवधान)

राव बीरेन्द्र सिंह: अगर इनकी तरह हम सारे अपनी सीटों पर खड़े हो जायें तो ठीक नहीं रहेगा। (व्यवधान) मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूँ कि अनुपासन कायम किया जाये।

श्री सभापति: मैं कोशिश कर रहा हूँ और आपके साथी भी बगैर बात के वाक आउट करते हैं। (व्यवधान)

राव बीरेन्द्र सिंह: बगैर बात के वाक आउट नहीं किया है (व्यवधान)

श्री सभापति: उनको बोलने के लिये आधा घंटा दिया
even then he staged a walk out.

राव बीरेन्द्र सिंह: क्या आप इसका बदला निकाल रहे हैं
(व्यवधान) अगर आप बदले तौर पर करना चाहते हैं तो ठीक है
(व्यवधान)

श्री सभापति: राव साहब, आप बैठ जाईये।

डा. मंगल सैन: चेयरमैन साहब, आपने राव साहब को कुछ नहीं कहा और उनका बार बार आपके ऊपर संदेह करना ठीक नहीं है, चेयर पर रिफ्लैक्शन नहीं करना चाहिए। चेयरमैन की बात को सिर झुका कर मानना चाहिए और हमारे हाउस का डैकोरम इसी बात पर निर्भर करता है। हां, मैं कह रहा था कि देना मे

बेकारी, बेरोजगारी, भूखमरी जो कांग्रेस सरकार की वजह से दे आ गई थी और जिसके कारण इस देश के गरीब लोगो ने, गांव मे रहने वाले बेकार और मेहनतकश लोगो ने, झुग्गी झोंपड़ियों मे रहने वाले गरीब आदमियों ने, कांग्रेस के कुत्सित को उखाड़ कर इनको खदेड़ दिया था और आज ये बार बार उछल रहे है.....

श्री भामदेव सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। डा. मंगल सैन जी ने मेरे सवाल का जवाब (विघ्न)

डा. मंगल सैन: सवाल का वक्त नहीं है, आप सवाल की बात कर रहे है, कोई मतलब की बात है (व्यवधान) आप खाहमखाह बोल रहे है। चेयरमैन साहब, बड़े अफसोस की बात है, अगर इसी तरह डिस्टरबेंस होती रही तो हाउस की कार्यवाही कैसे चलेगी ?

Mr. Chairman: The hon. Minister may please resume tomorrow, if he so likes.

The House now stands adjourned til 9.30 a.m. tomorrow, the 22nd March, 1979.

13.00 Hours

(The Sabha then *adjourned til 9.30 a.m. on Tuesday, the 22nd March, 1979.)